वर्ष 12 • अंक 307 • 18 पृष्ठ • मूल्य 5 रुपये

बुधवार 12 फरवरी 2020

कोलकाता, चंडीगढ़, **नई दिल्ली**, पटना, भोपाल, मुंबई, रायपुर और लखनऊ से प्रकाशित।

भारत का पहला संपूर्ण हिंदी आर्थिक अखबार

बिज़नेस स्टैंडर्ड

www.bshindi.com

पृष्ठ 6

पीटीए के दाम 10 फीसदी लुढ़के

पवन गोयनका पृष्ठ 2

सांगयोंग को उबारेगी महिंद्रा

डॉलर रु. 71.30 (अपरिवर्तित) | यूरो रु. 77.80 ▼ 30 पैसे | सोना (10ग्राम) रु 40461 ▼ 114 रुपये | सेंसेक्स 41216.10 ▲ 236.50 | निफ्टी 12107.90 ▲ 76.40 | निफ्टी फ्यूचर्स 12126.80 ▲ 18.90 | ब्रेंट क्रूड 54.00 डॉलर ▲ 01.00 डॉलर

एक नज़र

एडुकॉम्प, उसके निदेशकों पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने एडुकॉम्प सॉल्यूशंस, उसकी सहायक इकाइयों और निदेशकों पर कथित रूप से भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की अगुआई वाले 13 बैंकों के गठजोड़ से 1,955 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी देते हुए कहा कि सीबीआई ने आठ स्थानों पर छापेमारी भी की है। जांच एजेंसी ने एडुकॉम्प, उसके प्रबंध निदेशक शांतनु प्रकाश, गारंटर जगदीश प्रकाश, उसकी अनुषंगी एडु स्मार्ट सर्विसेज प्राइवेट लि. और निदेशकों विजय कुमार चौधरी और विनोद कुमार के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सीबीआई ने प्राथमिकी दर्ज कर दिल्ली, देहरादून और गुरुग्राम में एडुकॉम्प सॉल्यूशंस, एडु स्मार्ट और उसके निदेशकों के आठ परिसरों पर छापेमारी की है।

1 अप्रैल से दवा की श्रेणी में आएंगे चिकित्सा उपकरण

देश में बिकने वाले सभी चिकित्सा उपकरणों को 1 अप्रैल से दवा के तौर पर माना जाएगा और इनका विनियमन औषधि एवं कॉस्मेटिक्स अधिनियम, 1940 के तहत किया जाएगा। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने मंगलवार को इस बारे में अधिसूचना जारी की है। मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया है कि औषधि तकनीकी परामर्श बोर्ड से सलाह करने के बाद सभी चिकित्सा उपकरणों को 1 अप्रैल से दवा के तौर पर वर्गीकृत करने का निर्णय किया गया है। पृष्ठ 4

एक परियोजना दिवालिया तो पूरी कंपनी पर असर नहीं

राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील पंचाट (एनसीएलएटी) ने कहा है कि अगर किसी रियल एस्टेट कंपनी की एक परियोजना दिवालिया प्रक्रिया में जाती है तो पूरी कंपनी या उसकी अन्य परियोजना इसके दायरे में नहीं आएंगी। अपील पंचाट ने पहली बार रियल एस्टेट कंपनी के लिए ऐसी रिवर्स ऋणशोधन समाधान प्रक्रिया का आदेश दिया है ताकि बकाया वसूली के लिए ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवालिया संहिता के उपयोग को बढ़ावा नहीं मिले। अपील पंचाट ने कहा कि मकान खरीदार चाहें तो प्रवर्तक या समाधान पेशेवर से तीसरे पक्ष को फ्लैट बेचकर पैसा वापस लेने का अनुरोध कर सकता है।

आईडीबीआई बैंक को हुआ 5,763 करोड़ रुपये का घाटा

आईडीबीआई बैंक ने मंगलवार को कहा कि उसका तीसरी तिमाही का घाटा और बढ़कर 5,763.04 करोड़ रुपये हो गया है। बैंक का फंसे कर्ज का स्तर लगातार ऊंचा बना हुआ है। इससे पहले पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में बैंक का शुद्ध घाटा 4,185.48 करोड़ रुपये था। आईडीबीआई बैंक ने नियामकीय जानकारी में कहा है कि दिसंबर 2019 में समाप्त तिमाही में उसकी कुल आय बढ़कर 6,215.60 करोड़ रुपये हो गई जो कि एक साल पहले इसी अवधि में 6,190 करोड़ रुपये रही थी। पृष्ठ 3

अदाणी ट्रांसमिशन ने एईएमएल में बेचा हिस्सा

अदाणी ट्रांसमिशन ने अदाणी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई (एईएमएल) में अपनी 25.1 फीसदी हिस्सेदारी कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी को बेच दी है। यह सौदा 3,220 करोड़ रुपये में होने का अनुमान है। अदाणी ट्रांसमिशन ने कहा कि कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने अदाणी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई में 25.10 फीसदी हिस्सेदारी के अधिग्रहण को पूरा कर लिया है। पृष्ठ 3

व्यापार गोष्ठी

आयकर की दोहरी प्रणाली कितनी सुगम?

अपनी राय पासपोर्ट साइज फोटो और पूरे पते के साथ हमें इस पते पर भेजें :

बिज़नेस स्टैंडर्ड , नेहरू हाउस, 4 बहादुरशाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली-110002 फैक्स नंबर - 011-23720201
या फिर ई-मेल करें gosthi@bsmail.in
अपने विचार आप हमें bshindi.com पर भी भेज सकते हैं

आज का सवाल

क्या विदेश पैसे भेजने पर टीसीएस काटने का निर्णय सही है

www.bshindi.com **पर राय भेजें।**
आप अपना जवाब एसएमएस भी कर सकते हैं। यदि आपका जवाब हां है तो **BSP Y** और यदि न है तो **BSP N** लिखकर **57007** पर भेजें।

पिछले सवाल का नतीजा

क्या मुआवजा प्रतिपूर्ति पर केंद्र और राज्यों के बीच बढ़ेगी तकरार?	हां	33.33%
	नहीं	66.67%

दिल्ली के मतदाताओं ने फिर जताया केजरीवाल पर भरोसा, दहाई तक भी नहीं पहुंची भाजपा

दिल्ली में आप बाकी सब साफ

अर्चिस मोहन
नई दिल्ली, 11 फरवरी

आम आदमी पार्टी (आप) ने दिल्ली विधानसभा चुनावों के आज आए नतीजों में एक बार फिर शानदार प्रदर्शन करते हुए भारी जीत दर्ज हासिल की है। पार्टी ने इसे 'भाजपा की नफरत की राजनीति' के खिलाफ 'विकास की राजनीति' की जीत बताया है।

ताजा आंकड़ों के मुताबिक आप 70 सदस्यीय दिल्ली विधानसभा में 55 सीटें जीत चुकी है और 7 सीटों पर आगे चल रही है। 2015 में हुए पिछले विधानसभा चुनावों में आप ने 67 सीट जीती थी। इस बार पार्टी को 53.6 फीसदी वोट मिले हैं जो पिछली बार के 54.3 फीसदी से थोड़ा कम है।

भारतीय जनता पार्टी के खाते में 7 सीटें आई है और वह एक सीट पर आगे चल रही है। पिछले विधानसभा चुनावों में पार्टी केवल तीन सीट जीत पाई थी। हालांकि भाजपा का वोट प्रतिशत इस बार बढ़कर 38.5 फीसदी रहा जो पिछली बार 32.1 फीसदी था। भाजपा को इससे पहले झारखंड में भी हार का सामना करना पड़ा था और वह महाराष्ट्र में सरकार बनाने में नाकाम रही थी। पार्टी हरियाणा में भी बहुमत से दूर रह गई थी और उसे गठबंधन सरकार बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा था। आप को यह जीत ऐसे समय मिली है जब नागरिकता कानून में संशोधन के खिलाफ देश के कई इलाकों में प्रदर्शन हो रहा है। इसमें दिल्ली का शाहीन बाग भी शामिल है जिसे भाजपा ने इन चुनावों में जोरशोर से मुद्दा बनाया था और दिल्ली के मतदाताओं से 'आतंकवादियों' को सत्ता से बाहर करने की अपील की थी।

पिछले महीने भाजपा अध्यक्ष का पद छोड़ने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इन चुनावों को अपनी प्रतिष्ठा का विषय बना लिया था। उन्होंने दिल्ली में व्यापक चुनाव प्रचार किया, कई जनसभाओं को संबंधित किया और घर-घर जाकर पर्चे भी बांटे। प्रचार के दौरान आप और उसके नेता तथा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने नागरिकता संशोधन कानून के विवादास्पद मुद्दे से बचने की कोशिश की। इसके बजाय उन्होंने आप सरकार द्वारा दिल्ली में किए गए कामों को मुद्दा बनाया। आप की जीत के बाद सभी विपक्षी नेताओं ने केजरीवाल सरकार के विकास कार्यों की सराहना की। आप की जीत से क्षेत्रीय दलों का भी भाजपा के खिलाफ मनोबल बढ़ा है। 1998 से 2013 तक लगातार तीन बार दिल्ली में राज करने वाली कांग्रेस एक बार फिर अपना खाता नहीं खोल पाई। पार्टी का वोट शेयर भी 9.6 फीसदी से घटकर 4.27 फीसदी रह गया। पार्टी के केवल तीन उम्मीदवार ही जमानत बचा पाए।

■ संबंधित खबर : पृष्ठ 18

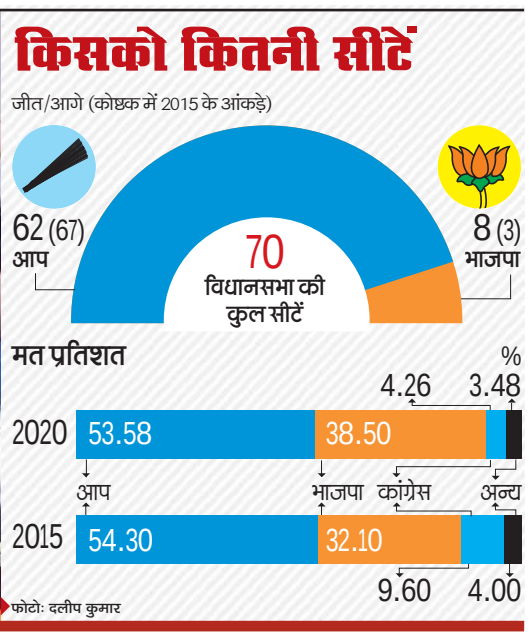

फोटो: दलीप कुमार

अर्थव्यवस्था में दिख रहे सुधार के संकेत

अरूप रायचौधरी
नई दिल्ली, 11 फरवरी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था धीरे-धीरे आर्थिक सुस्ती से बाहर निकल रही है। उन्होंने कहा कि देश के आर्थिक हालात दोबारा पटरी पर लौटने के संकेत मिलने शुरू हो गए हैं। मंगलवार को संसद के ऊपरी सदन राज्य सभा में बजट पर चर्चा के दौरान सीतारमण ने कहा कि 2008-09 के वैश्विक आर्थिक संकट के बाद मनमोहन सिंह सरकार ने जो गलती की थी, उनकी सरकार वैसी गलती नहीं करेगी। उन्होंने संसद के निचले सदन लोकसभा में कहा, 'सात ऐसे महत्त्वपूर्ण संकेत हैं, जो अर्थव्यवस्था में सुधार दर्शा रहे हैं।' उन्होंने संसद के दोनों सदनों में इन संकेतों का जिक्र किया।

- वित्त मंत्री ने संसद में कहा कि अर्थव्यवस्था लौट रही है पटरी पर
- 2019-20 में एफडीआई में आई है तेजी
- जीएसटी संग्रह कम से कम छह बार 1 लाख करोड़ रुपये से रहा है अधिक

सीतारमण ने कहा कि नवंबर के अंत में 2019-20 के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) 24.4 अरब डॉलर दर्ज किया गया, जो 2018-19 में अप्रैल-नवंबर अवधि में 21.1 अरब डॉलर रहा था। वित्त मंत्री ने कहा कि अप्रैल-नवंबर 2019-20 की अवधि में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के मद में देश में 12.6 अरब डॉलर रकम आई। बकौल सीतारमण, पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में यह आंकड़ा 8.7 अरब डॉलर रहा था। उन्होंने कहा कि विभिन्न ढांचागत परियोजनाओं में निवेश के लिए नैशनल इन्वेस्टमेंट ऐंड इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड को 22,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। सीतारमण ने कहा कि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, विनिर्माण एवं सेवाओं पर पर्चेजिंग मैनेजर्स सूचकांक, विदेशी मुद्रा और कर संग्रह सभी आर्थिक सुधार के संकेत दे रहे हैं।

वित्त मंत्री ने कहा, 'जनवरी में सकल वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) राजस्व 1.10 लाख करोड़ रुपये रहा था। वित्त वर्ष 2020 में सकेल जीएसटी राजस्व कम से कम छह बार 1 लाख करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर चुका है।' उन्होंने कहा कि सरकार की नजर चार प्रमुख बिंदुओं निजी निवेश, निर्यात, निजी एवं सार्वजनिक उपभोग पर रहेगा। निर्यात के संबंध में सीतारमण ने कहा कि इन क्षेत्रों को मजबूती देने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं, जिनमें कर वापसी योजना और निर्यातकों को अधिक ऋण शामिल हैं। उन्होंने कहा कि निर्यात उत्पादों पर शुल्क एवं करों में कमी की योजना मौजूदा मर्चेंडाइज फ्रॉम इंडिया स्कीम (एमईआईएस) की जगह लेगी। एमईआईएस वैश्विक व्यापार नियमों के अनुपालन के लिहाज से सटीक नहीं माना जाती है।

वित्त मंत्री ने कहा, 'आरओडीटीईपी मौजूदा सभी योजनाओं के मुकाबले निर्यातकों को अधिक प्रोत्साहन देगी। मैं यह स्पष्ट करना चाहती हूं कि आरओडीटीईपी निर्यातकों को अधिक प्रोत्साहन देगी और उन्हें राहत मुहैया कराने में भी मौजूदा योजनाओं के मुकाबले कारगर साबित होगी।' सीतारमण ने यह भी कहा कि निर्यात क्षेत्र को अधिक ऋण मुहैया कराने के लिए आरबीआई ने पात्र निर्यातकों के लिए ऋण आवंटन सीमा बढ़ा दी है। उन्होंने कहा, 'इसे प्रति कर्जदाता 25 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 40 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इसके साथ ही 100 करोड़ रुपये से अधिक कारोबार करने की मौजूदा शर्त भी पूरी तरह हटा दी गई है।'

विदेश पैसे भेजने पर कर से बढ़ी चिंता

श्रीमी चौधरी
नई दिल्ली, 11 फरवरी

विदेश पैसे भेजने के लिए बजट में नया कर लगाने के प्रस्ताव को लेकर दोहरा कराधान का डर सता रहा है क्योंकि आयकर चुकाने के बाद भी विदेश पैसा भेजने पर स्रोत पर कर संग्रह (टीसीएस) के तौर पर 5 फीसदी की कटौती की जाएगी। सूत्रों के अनुसार नए कराधान से सरकार को हर महीने करीब 500 से 600 करोड़ रुपये अग्रिम मिलेंगे।

आम बजट 2021 में सरकार ने प्रस्ताव किया है कि बैंकों को किसी व्यक्ति से भारतीय रिजर्व बैंक के उदार धन प्रेषण योजना के तहत विदेश भेजने के लिए 7 लाख रुपये या उससे अधिक पैसे मिलते हैं तो उसे उक्त राशि का 5 फीसदी टीसीएस के तौरपर काटना होगा। यह प्रस्ताव आयकर विभाग द्वारा विस्तृत विश्लेषण के बाद किया गया था। अध्ययन से पता चला था कि कई लोग धनशोधन के लिए इस उपाय का दुरुपयोग कर रहे थे। इसके साथ ही यह पाया गया था कि इसका ज्यादातर दुरुपयोग 7 लाख रुपये से अधिक पैसे भेजने वाले लोग करते हैं। इसलिए 7 लाख रुपये की सीमा तय की गई है।

- **7** लाख रुपये या उससे अधिक विदेश भेजने पर **5** फीसदी टीसीएस का प्रस्ताव
- आयकर के बाद इस तरह के कर से दोहरे कराधान की आशंका
- जांच एजेंसियों ने फर्जी तरीके से बड़े पैमाने पर विदेश पैसे भेजने की जताई थी आशंका

स्रोत पर कर संग्रह (टीसीएस) विशिष्ट वस्तुओं की बिक्री करने वालों द्वारा खरीदारों से वसूला जाता है और सरकार को उसका भुगतान किया जाता है। एक अधिकारी ने कहा कि टीसीएस के मामले में करदाता आयकर रिटर्न में रिफंड का दावा कर सकते हैं, इसलिए यह दोहरा कराधान नहीं है। लेकिन दूसरी ओर इस प्रक्रिया से अनुपालन का बोझ बढ़ेगा क्योंकि रिफंड का दावा करना जटिल होगा। उनके अनुसार हर लेनदेन स्थायी खाता संख्या (पैन) में दर्ज होगा और धन प्रेषण का रिकॉर्ड आरबीआई के पास मौजूद होगा।

इस बीच, उद्योग के भागीदारों और कारोबारी जगत के एक धड़े ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ हालिया बैठक में नए कर को लेकर समीक्षा की मांग की है। उद्यमियों की राय है कि आरबीआई योजना के तहत विदेश भेजे जाने वाला धन वैध होता है और यह शिक्षा एवं निवेश के लिए भेजे जाते हैं। इसलिए इस पर कर लगाना करदाताओं पर अतिरिक्त बोझ की तरह है। इसके साथ ही रिफंड मिलने तक कार्यशील पूंजी की भी दिक्कत हो सकती है।

आरबीआई की योजना के तहत कोई भी व्यक्ति सालाना 2,50,000 डॉलर तक विदेश भेज सकता है और 2018 से ही इसकी जांच की जा रही है। जांच एजेंसियों ने पाया कि थाईलैंड, दुबई, सिंगापुर और हॉन्ग कॉन्ग जैसे देशों में काफी मात्रा में देश से पैसे भेजे गए हैं।

अनुमान के मुताबिक इन देशों में 2018 में करीब 20 से 30 हजार करोड़ रुपये भेजे गए हैं। थाईलैंड में ही करीब 5,000 करोड़ रुपये भेजे गए हैं। नियामकीय जांच से बचने के लिए फॉरेक्स डीलरों ने इस योजना के तहत हजारों फर्जी बिल बनाए थे। जांच एजेंसियों ने बड़े पैमाने पर विदेश पैसे भेजे जाने के मामले को लेकर 2019 में वित्त मंत्रालय और आरबीआई के समक्ष चिंता जताई थी। एजेंसियों ने इसकी तत्काल जांच करने और उदार धन प्रेषण योजना को सख्त बनाने की मांग की थी।

कारोबारी क्षेत्रों में चला झाड़ू भाजपा को भी मिला साथ

रामवीर सिंह गुर्जर
नई दिल्ली, 11 फरवरी

- ज्यादातर कारोबारी इलाकों और कारोबारी बहुल सीटों पर जीती आप
- भाजपा ने आठ सीटें जीती जिनमें 4 कारोबारी बहुल

आम आदमी पार्टी (आप) ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत दर्ज की है। ज्यादातर कारोबारी इलाकों और कारोबारी बहुल सीटों पर आप उम्मीदवारों को जीत मिली है। लेकिन बुरा प्रदर्शन करने वाली भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को सबसे ज्यादा सहारा कारोबारी बहुल सीटों पर ही मिला। भाजपा 8 सीटों पर जीतती दिख रही है जिनमें 4 सीटें कारोबारी बहुल मानी जाती हैं। हालांकि भाजपा द्वारा उम्मीदवार बनाए गए दिल्ली के दो प्रमुख कारोबारी नेता चुनाव हार गए।

दिल्ली में 15 से 20 सीटों पर कारोबारी वोट निर्णायक भूमिका में हैं। कारोबारी अनुमान के मुताबिक दिल्ली के 15 लाख कारोबारियों के 20 से 25 लाख वोट हैं। आप ने राजौरी गार्डन, शालीमार बाग, सदर बाजार, करोलबाग, मॉडल टाउन, शाहदरा, राजेंद्र नगर, वजीरपुर और आदर्श नगर जैसी कारोबारी बहुल सीटों पर जीत हासिल की। भाजपा को गांधीनगर, लक्ष्मीनगर, रोहिणी और विश्वास नगर कारोबारी बहुल सीटों पर जीत मिली। भाजपा द्वारा जीती गई ये सीटें कारोबारियों के लिए अहम चुनावी मुद्दा सीलिंग से भी प्रभावित हैं। भाजपा ने इस विधानसभा चुनाव में कारोबारियों की राजनीति करने वाले दो प्रमुख कारोबारी नेताओं को चुनाव में उतारा था। लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। कारोबारी संगठन कैट से जुड़े भाजपा उम्मीदवार रमेश खन्ना कारोबारी बहुल सीट राजौरी गार्डन से चुनाव हार गए।

एचएएल ने की बल्क दवा बनाने की पेशकश

सोहिनी दास
मुंबई, 11 फरवरी

- 70 फीसदी बल्क दवा का चीन से होता है आयात
- किण्वन आधारित करीब सभी एपीआई का आयात
- एंटीबायोटिक और विटामिन बनाने में होता है इस्तेमाल
- एचएएल ने इन्फ्रा में सुधार के लिए सरकार को भेजा प्रस्ताव

चीन में कोरोनावायरस के प्रकोप और करीब 1000 से अधिक लोगों की मौत ने भारतीय दवा उद्योग की मुश्किलें बढ़ा दी है जो कच्चे माल के लिए काफी हद तक चीन पर निर्भर है। इस स्थिति ने एक तरह से भारत की कमजोरी को भी उजागर कर दिया है। इस स्थिति से निपटने के लिए देश में दवा क्षेत्र की सबसे पुरानी सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड (एचएएल) ने किण्वन आधारित बल्क दवाओं के लिए चीन पर निर्भरता कम करने के वास्ते सरकार को एक प्रस्ताव सौंपा है। पुणे स्थित इस कंपनी का कहना है कि अगर उसे अपने बुनियादी ढांचे को अपग्रेड करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है तो वह देश में इस तरह की दवाओं की जरूरत का 50 फीसदी तक बना सकती है।

मोटे अनुमान के मुताबिक भारत 67 से 70 फीसदी बल्क दवाएं यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इनग्रेडिएंट्स (एपीआई) चीन से आयात करता है। लेकिन भारत किण्वन आधारित करीब सभी एपीआई का आयात चीन से करता है। इन बल्क दवाओं का इस्तेमाल पेंसिलिन जैसे एंटीबायोटिक्स और विटामिन बनाने में होता है।

सरकार वित्तीय संकट से जूझ रही एचएएल को बेचने की योजना बना रही है। यह देश की एकमात्र सार्वजनिक कंपनी है जो किण्वन आधारित एपीआई बनाती है। सूत्रों के मुताबिक 2003 में अंतिम बार ये दवाएं बनाई थीं।

सूत्रों के मुताबिक एचएएल ने कुछ दिन पहले दवा विभाग को एक प्रस्ताव भेजा है। इसमें कहा गया है कि उसके संयंत्रों और मशीनरी को दुरुस्त करने की जरूरत है। इसके बाद वह एपीआई आधारित दवाएं बना सकती है। अगर कंपनी को सैद्धांतिक मंजूरी मिलती है तो वह इस योजना पर काम शुरू कर सकती है। कंपनी के विनिर्माण ढांचे को अपग्रेड करने के लिए चार से छह महीने का समय लगेगा। लेकिन इससे चीन से आयात होने वाली एपीआई के लिए स्थायी समाधान मिल सकता है और इस तरह एचएएल का उद्धार भी हो सकता है। एक सूत्र ने कहा, अगर यह योजना मंजूर होती है तो इससे भारत की एपीआई के लिए चीन पर निर्भरता की समस्या का स्थायी समाधान मिल सकता है। शुरुआत में कंपनी के उत्पादन से भारत की 30 से 40 फीसदी जरूरत पूरी हो सकती है। बाद में इसे बढ़ाकर 50 फीसदी तक किया जा सकता है।

मोटे तौर पर भारत में किण्वन आधारित एपीआई की सालाना खपत करीब 2000 टन है। एचएएल के पुणे संयंत्र से पूरी क्षमता के साथ 1200 टन दवा बनाई जा सकती है। लेकिन इसके लिए केंद्र को एलएएल के बुनियादी ढांचे के अपग्रेड करने के लिए निवेश को मंजूरी देनी होगी। सूत्रों के मुताबिक हर उत्पाद के लिए करीब 50 करोड़ रुपये के निवेश की जरूरत है और एचएएल में करीब 12 उत्पाद बनाए जा सकते हैं।

सूत्रों का मानना है कि सरकार के पास चीन पर निर्भरता कम करने के लिए सीमित विकल्प हैं और एचएएल में निवेश उनमें से एक हो सकता है।

गुजरात में बल्क दवा बनाने वाली एक इकाई के मालिक ने कहा, 'बल्क दवाएं बनाने वाली स्थानीय कंपनियां भी किण्वन आधारित एपीआई बना सकती हैं। लेकिन उसमें एक पेच है। इसके लिए उन्हें अपने मौजूदा पोर्टफोलियो में बदलाव करने और उत्पादन शुरू करने के लिए कम से कम 3 से 5 महीने का समय चाहिए। दूसरा, मौजूदा संकट के खत्म होने के बाद उनका भविष्य अनिश्चित होगा।'

खबरों में रहे स्टॉक

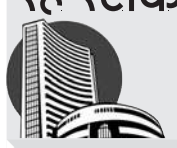

जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया

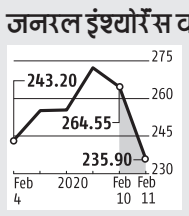

तीसरी तिमाही में 1,035 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा

₹ 264.55 पिछला बंद भाव
₹ 235.90 आज का बंद भाव
▼ 10.83 %

गेल (इंडिया)

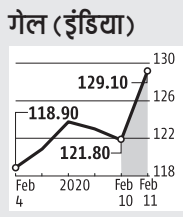

तीसरी तिमाही में कर पूर्व लाभ 65 फीसदी बढ़ा

₹ 121.80 पिछला बंद भाव
₹ 129.10 आज का बंद भाव
▲ 6.00 %

शिल्पा मेडिकेयर

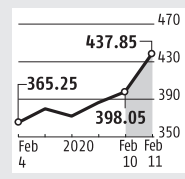

तीसरी तिमाही में 65 करोड़ रुपये का कर पूर्व लाभ

₹ 398.05 पिछला बंद भाव
₹ 437.85 आज का बंद भाव
▲ 10.00 %

बीएएसएफ इंडिया

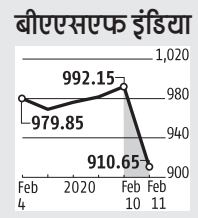

मास्टर बिल्डर्स को बेचा निर्माण रसायन कारोबार

₹ 992.15 पिछला बंद भाव
₹ 910.65 आज का बंद भाव
▼ 8.21 %

हिम्मतसिंगका सीड

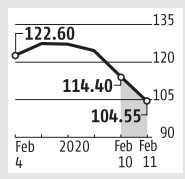

तीसरी तिमाही में लाभ 95 फीसदी घटने से दो दिनों में 17 फीसदी लुढ़का शेयर

₹ 114.40 पिछला बंद भाव
₹ 104.55 आज का बंद भाव
▼ 8.61 %

संक्षेप में

मेकमाईट्रिप के ग्रुप सीईओ बने राजेश मैगो

ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी मेकमाईट्रिप के संस्थापक दीप कालरा ने ग्रुप सीईओ का पद छोड़ दिया है और अब उनकी जगह कंपनी के सह-संस्थापक और भारत के सीईओ राजेश मैगो लेंगे। कालरा अब समूह के कार्यकारी चेयरमैन की भूमिका में पूरा समय रणनीतिक पहल पर लगाएंगे, जिसमें उत्पादों का नवोन्मेष व विस्तार, भौगोलिक स्तर पर प्रगति, कारोबारी मॉडल का नवोन्मेष और कॉरपोरेट डेवलपमेंट शामिल है। कंपनी ने यूएस सिक्योरिटीज ऐंड एक्सचेंज कमीशन को भेजी सूचना में ये बातें कही। मेकमाईट्रिप नैसडेक पर सूचीबद्ध है। *बीएस*

मूडीज ने इंडसइंड बैंक का परिदृश्य किया नकारात्मक

रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने निजी क्षेत्र के इंडसइंड बैंक के परिदृश्य को स्थिर से घटाकर नकारात्मक कर दिया है। बैंक की संपत्ति की गुणवत्ता में और गिरावट के मद्देनजर रेटिंग एजेंसी ने यह कदम उठाया है। मूडीज ने नोट में कहा कि निजी क्षेत्र के बैंक की रेटिंग या साख को बीएए-3-पी-3 पर कायम रखा गया है। बीएए3 निवेश श्रेणी में सबसे निचली रेटिंग है। *भाषा*

बीएचईएल का मुनाफा 17 फीसदी घटा

सार्वजनिक क्षेत्र की इंजीनियरिंग कंपनी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि. (भेल) का चालू वित्त वर्ष की दिसंबर, 2019 को समाप्त तीसरी तिमाही का एकीकृत शुद्ध लाभ 17 फीसदी घटकर 161.81 करोड़ रुपये रह गया। आमदनी घटने से कंपनी का मुनाफा कम हुआ है। इससे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में कंपनी ने 196.43 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित किया था। कंपनी ने कहा कि तिमाही के दौरान उसकी कुल आय घटकर 5,827.74 करोड़ रुपये रह गई। *भाषा*

बीईएमएल का एकीकृत लाभ घटा

बीईएमएल लिमिटेड का एकीकृत शुद्ध लाभ चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में 90.8 फीसदी घटकर 4.24 करोड़ रुपये रहा। इससे पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में कंपनी का एकीकृत शुद्ध लाभ 46.20 करोड़ रुपये था। कंपनी को पहले भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के तौर पर जाना जाता था। *भाषा*

सांगयोंग को उबारेगी महिंद्रा

सांगयोंग मोटर के पुनरुद्धार के लिए बनाई 3 साल की योजना

शैली सेठ मोहिले
मुंबई, 11 फरवरी

सांगयोंग मोटर के लिए जिंदगी पूरी रफ्तार में है। कोरिया की इस संकटग्रस्त वाहन कंपनी का नियंत्रण महिंद्रा ऐंड महिंद्रा के पास आने के करीब एक दशक बाद आनंद महिंद्रा के नेतृत्व वाली कंपनी ने तीन वर्षों में उसके पुनरुद्धार के लिए एक योजना तैयार की है। सांगयोंग मोटर की बिक्री घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय बाजारों में लगातार घट रही है और उसका नुकसान बढ़ रहा है। महिंद्रा ने मार्च 2011 में सांगयोंग में 70 फीसदी हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया था।

अपनी ताजा योजना के तहत महिंद्रा इस संकटग्रस्त कंपनी के पुनरुद्धार के लिए 450 से 500 अरब कोरियाई वोन यानी करीब 38 से 42.5 करोड़ डॉलर का निवेश करेगी। ग्राहकों का रुझान डीजल से पेट्रोल वाहनों की ओर होने, निर्यात में भारी गिरावट और वैश्विक आर्थिक मंदी के कारण कंपनी को तगड़ा झटका लगा है।

निवेश के लिए आधी रकम इक्विटी के जरिये और शेष रकम बैंक ऋण के जरिये जुटाने की योजना है। रेक्सटन एसयूवी बनाने वाली इस कंपनी ने कैलेंडर वर्ष 2019 में 300 अरब कोरियाई वोन का घाटा दर्ज किया था जो उसका अब तक का सर्वाधिक घाटा है। महिंद्रा ऐंड महिंद्रा के प्रबंध निदेशक पवन गोयनका ने आज कहा, 'हमने तीन साल की एक योजना बनाई है जिसे सांगयोंग के बोर्ड से मंजूरी मिल गई है। हम इसे 2022 तक मुनाफे में लाना चाहते हैं।'

महिंद्रा की इस योजना में जबरदस्त तरीके से लागत घटाने और हर साल कम से कम 80 से 90 अरब कोरियाई वोन बचाने की बात भी कही गई है। गोयनका ने कहा कि यह दो साल की परियोजना होगी जिससे कंपनी के परिचालन मुनाफा मार्जिन में करीब 3 फीसदी का सुधार होगा। उन्होंने कहा कि ताजा निवेश करने के अलावा महिंद्रा एवं साझेदार फोर्ड के साथ तालमेल बिठाना भी इस रणनीति का एक अहम हिस्सा होगा। उन्होंने कहा, 'हमारे आकलन के अनुसार, पूरी तरह सुधार होने में 450 से 500 अरब कोरियाई वोन की वित्तीय मदद की दरकार होगी।' महिंद्रा इसके लिए कर्जदाताओं से बातचीत कर रही है। इसके अलावा पुनरुद्धार योजना तैयार करने के लिए कंपनी बाहरी सलाहकारों से भी विचार-विमर्श कर रही है।

रिलायंस सिक्योरिटीज के उपाध्यक्ष (अनुसंधान) मितुल शाह ने कहा कि इस पुनरुद्धार योजना को लागू करना आसान नहीं होगा। उन्होंने कहा, 'वैश्विक बिक्री में तेजी के दौरान कंपनी अपने बेहतरीन समय में भी अपेक्षित परिणाम हासिल नहीं कर पाई और ऐसे में वैश्विक मंदी एवं उथल-पुथल के दौर में पुनरुद्धार योजना को लागू करना आसान नहीं होगा। इसलिए इस योजना से निवेशकों में अधिक भरोसा नहीं दिखेगा।'

दिसंबर तिमाही में महिंद्रा ऐंड महिंद्रा का मुनाफा एक साल पहले की समान अवधि के मुकाबले 73 फीसदी घट गया जिसे नुकसान के लिए 380 करोड़ रुपये के एकमुश्त प्रावधान से बल मिला।

महिंद्रा का शुद्ध लाभ 85 फीसदी घटा

वाहन बनाने वाली दिग्गज कंपनी महिंद्रा का एकीकृत शुद्ध लाभ दिसंबर 2019 की तिमाही में 85 फीसदी की गिरावट के साथ 200 करोड़ रुपये रह गया। मांग में कमी के कारण मुनाफा प्रभावित हुआ। कंपनी का राजस्व हालांकि 4 फीसदी टूटकर 25,303 करोड़ रुपये रह गया, वहीं मार्जिन 13.2 फीसदी के मुकाबले सुधरकर 14.8 फीसदी रहा।

एकल आधार पर भी शुद्ध मुनाफा 73 फीसदी घटकर 380 करोड़ रुपये रह गया, वहीं राजस्व सिर्फ 6 फीसदी की गिरावट के साथ 12,120 करोड़ रुपये रहा। कंपनी की कुल बिक्री 8 फीसदी घटकर 1,23,353 वाहन रही क्योंकि ट्रैक्टरों की बिक्री 6 फीसदी घटकर 81,453 और निर्यात 22 फीसदी घटकर 9,633 वाहन रहा। इसकी तुलना में वाहन उद्योग की बिक्री दिसंबर तक 7 फीसदी घटी है। *बीएस*

दोपहिया और वाणिज्यिक वाहन निर्माताओं को सुधार की उम्मीद

टी ई नरसिम्हन
चेन्नई, 11 फरवरी

जनवरी 2018 में वाणिज्यिक वाहन व दोपहिया क्षेत्र में एक साल पहले की समान अवधि के मुकाबले 39 फीसदी और 33 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज हुई थी, लेकिन जनवरी 2020 में जनवरी 2019 के मुकाबले इनमें क्रमश: 14.04 फीसदी व 16.06 फीसदी की गिरावट दर्ज हुई।

इन दोनों क्षेत्रों पर अर्थव्यवस्था की मंदी और ग्रामीण बिक्री, नियमन में बदलाव का दबाव बना हुआ है। उद्योग के प्रतिनिधियों ने कहा कि साल की दूसरी छमाही में उन्हें सुधार की उम्मीद है क्योंकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था पटरी पर आ रही है और सरकार ने अर्थव्यवस्था की मजबूती व धारणा में सुधार के लिए कई परियोजनाओं की घोषणा की है।

सायम के आंकड़ों के मुताबिक, जनवरी 2017 में वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री 61,305 इकाई रही थी, जो जनवरी 2018 में बढ़कर 85,660 इकाई पर पहुंच गई। जनवरी 2019 में यह बढ़कर 87,591 वाहन रही। हालांकि जनवरी 2020 में यह घटकर 75,289 वाहन रह गई। दोपहिया की बिक्री जनवरी 2017 के 12,62,140 वाहन के मुकाबले जनवरी 2018 में 16,84,066 पर पहुंच गई। हालांकि जनवरी 2019 के बाद से इसमें गिरावट जारी है और जनवरी 2020 में यह 13,41,005 वाहन रह गई।

अर्थव्यवस्था में सुस्ती के अलावा बुनियादी ढांचे पर खर्च में नरमी, मालभाड़े की दर में गिगरावट, ऐक्सल लोड के संशोधित नियम, जीएसटी की दरें, एनबीएफसी का संकट, उत्सर्जन नियम आदि का वाणिज्यिक वाहन क्षेत्र पर असर पड़ा।

अशोक लीलैंड को उम्मीद है कि मध्यम व भारी वाणिज्यिक वाहन उद्योग वित्त वर्ष 2019-20 की समाप्ति 2 लाख की कुल बिक्री के साथ करेगा, जो पिछले साल के मुकाबले करीब 46.23 फीसदी की गिरावट दर्शाता है। हालांकि उसे उम्मीद है कि स्थिति में सुधार होगा।

अशोक लीलैंड के प्रबंध निदेशक व सीईओ विपिन सोढ़ी ने कहा, बजट में कृषि, सिंचाई और ग्रामीण विकास पर 2.83 लाख करोड़ रुपये के आवंटन से वाणिज्यिक वाहन उद्योग को मदद मिलेगी क्योंकि यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाएगा। पांच साल में बुनियादी ढांचा पर 100 लाख करोड़ रुपये खर्च करने का बजट प्रस्ताव वाणिज्यिक वाहनों की मांग में इजाफा करेगा।

उन्होंने कहा, आर्थिक गतिविधियां और रोजगार सृजन वस्तुओं की मांग व उपभोग में इजाफा करेगा और इससे ट्रकों के मालभाड़े में भी सुधार होगा।

हीरो मोटोकॉर्प के मुख्य वित्त अधिकारी निरंजन गुप्ता ने कहा, आर्थिक मंदी के बीच दोपहिया उद्योग में चुनौतियां बनी हुई हैं। शुरुआती संकेतक मसलन सकारात्मक रबी फसल ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर नजर आ र ही है, जो उद्योग की मदद कर सकता है। गुप्ता ने कहा, आम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की घोषणा से अर्थव्यवस्था में सुधार होगा। हालांकि दोपहिया उद्योग में स्थायी सुधार में थोड़ा वक्त लगेगा।

जनवरी के आंकड़ों की तुलना

महीना	दोपहिया	यात्री वाहन	वाणिज्यिक वाहन	तिपहिया	कुल
जनवरी 17	12,62,140	2,65,389	61,305	31,345	16,20,179
जनवरी 18	16,84,066	2,85,477	85,660	62,543	21,17,746
जनवरी 19	15,97,528	2,80,091	87,591	54,053	20,19,253
जनवरी 20	13,41,005	2,62,714	75,289	60,903	17,39,975*

* तिमाही बिक्री समेत

स्रोत : सायम

आईटीसी ने सिगरेट कीमतों में किया 10 से 20 फीसदी इजाफा

अभिषेक रक्षित
कोलकाता, 11 फरवरी

- **अमेरिकन क्लब कूल फ्रेश टेस्ट की 20 सिगरेट वाली डिब्बी की कीमत 10 फीसदी बढ़कर 220 रुपये हो गई है**
- **नेवी कट फिल्टर की 10 सिगरेट वाली डिब्बी की कीमत करीब 16 फीसदी बढ़कर 80 रुपये हो गई**
- **फ्लेक फिल्टर की कीमत करीब 14 फीसदी बढ़कर 80 रुपये हो गई**
- **फ्लेक स्पेशन फिल्टर, फ्लेक ब्लू स्पेशल फिल्टर और वेव कूल मिंट की कीमतों में 20 फीसदी का इजाफा किया गया**

केंद्रीय बजट में इस साल राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक शुल्क (एनसीसीडी) में इजाफे की घोषणा के बाद सिगरेट बाजार की अग्रणी कंपनी आईटीसी ने अपने सभी सिगरेट ब्रांड की कीमतों में 10 से 20 फीसदी के दायरे में मूल्य वृद्धि की घोषणा की है। यह वृद्धि सभी बाजारों के लिए लागू होगी। एनसीसीडी में वृद्धि से सिगरेट पर कराधान बढ़ गया। विनिर्माताओं के पास बढ़ी हुई लागत का वहन खुद करने अथवा उसका बोझ ग्राहकों के कंधों पर डालने का विकल्प है।

आईटीसी के प्रवक्ता ने कहा, 'तमाम ब्रांड की सिगरेट की कीमतों में संशोधन किया गया है।' केंद्रीय बजट के बाद सिगरेट की कीमतों में यह पहला इजाफा है।

सूत्रों ने कहा कि अमेरिकन क्लब कूल फ्रेश टेस्ट की 20 सिगरेट वाली डिब्बी की कीमत 10 फीसदी बढ़कर 220 रुपये हो गई है। नेवी कट फिल्टर की 10 सिगरेट वाली डिब्बी की कीमत करीब 16 फीसदी बढ़कर 80 रुपये हो गई। जबकि फ्लेक फिल्टर की कीमत करीब 14 फीसदी बढ़कर 80 रुपये हो गई। इसी प्रकार, फ्लेक स्पेशन फिल्टर, फ्लेक ब्लू स्पेशल फिल्टर और वेव कूल मिंट की कीमतों में 20 फीसदी का इजाफा किया गया है।

अन्य जिन ब्रांड की सिगरेट के दाम बढ़ाए गए हैं उनमें गोल्ड फ्लेक सुपर स्टार और ड्यूक स्पेशल फिल्टर शामिल हैं।

सिगरेट कीमतों में की गई हालिया वृद्धि पिछले 2-3 वर्षों में आईटीसी द्वारा की गई सबसे तगड़ी वृद्धि में शामिल है। पिछले साल कंपनी ने कुछ अन्य क्षेत्रीय ब्रांड की कीमतों बढ़ोतरी के अलावा ब्रिस्टल, कैप्सटन और फ्लेक एक्सेल की कीमतों में 7 से 14 फीसदी के दायरे में इजाफा किया था जबकि 2017 में सिगरेट कीमतों में 6 से 7 फीसदी की वृद्धि हुई थी।

हालांकि 2016 में कंपनी ने अपने सिगरेट पोर्टफोलियो में चुनिंदा ब्रांड के दाम बढ़ाए थे। उस दौरान क्लासिक और गोल्ड फ्लेक किंग्स ब्रांड की कीमतों में 13 फीसदी का इजाफा किया गया था ताकि उत्पाद शुल्क में बढ़ोतरी का भार ग्राहकों के कंधों पर डाला जा सके। जबकि इससे एक साल पहले कीमतों में 12 से 21 फीसदी वृद्धि की गई थी।

गॉडफ्रे फिलिप्स की हिस्सेदारी बढ़ी

अभिषेक रक्षित
कोलकाता, 11 फरवरी

ऐसे समय में जब कमजोर उपभोक्ता मांग के कारण प्रमुख सिगरेट कंपनियों की वृद्धि रफ्तार सुस्त पड़ गई है, गॉडफ्रे फिलिप्स ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के दौरान अपनी मात्रात्मक बिक्री में 13.1 फीसदी की वृद्धि दर्ज की है। इससे कंपनी की बाजार हिस्सेदारी में 1 फीसदी का इजाफा हुआ।

कंपनी के सीईओ भीष्म वढेरा ने ने तीसरी तिमाही के वित्तीय नतीजे जारी करने के बाद विश्लेषकों से बातचीत में कहा, 'गॉडफ्रे फिलिप्स ने पिछले नौ महीने के दौरान घरेलू सिगरेट बिक्री में 13.1 फीसदी की दमदार वृद्धि दर्ज की और बेहतर उत्पाद पोर्टफोलियो के साथ प्राप्तियों में भी सुधार हुआ। घरेलू सिगरेट बाजार में हमारी हिस्सेदारी 11.9 फीसदी से बढ़कर 12.9 फीसदी हो गई।'

एडलवाइस सिक्योरिटीज के कार्यकारी उपाध्यक्ष (संस्थागत इक्विटी) अबनीश रॉय ने कहा कि अप्रैल से दिसंबर 2019 की अवधि में बाजार की अग्रणी कंपनी आईटीसी की सिगरेट बिक्री में 2.5 से 3 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई। जबरदस्त ध्रुवीकरण वाले देश के सिगरेट बाजार में आईटीसी की बाजार हिस्सेदारी तीन चौथाई है।

सूत्रों के अनुसार, बेहतर उत्पाद पोर्टफोलियो के अलावा गॉडफ्रे फिलिप्स की सिगरेट बिक्री को नए लॉन्च और उसके प्रमुख ब्रांड मार्लबोरो के नए बाजारों में प्रवेश से रफ्तार मिली। रॉय ने कहा, 'मार्लबोरो सिगरेट अन्य ब्रांडों के मुकाबले काफी तेजी से विकास कर रही है और यह नए बाजारों में दस्तक दे रही है।'

वढेरा के अनुसार, कंपनी ने अधिक संभावना वाले दक्षिण भारतीय बाजारों में स्थानीय बिक्री एवं वितरण नेटवर्क तैयार करते हुए अपने सिगरेट कारोबार आगे और रफ्तार देने की योजना बनाई है। हालांकि अमेरिका की 2.8 अरब डॉलर के कारोबार वाली कंपनी मोदी एंटरप्राइजेज की यह प्रमुख कंपनी ने भारत में मार्लबोरो के वितरण एवं विनिर्माण के लिए लाइसेंस हासिल किया है। इसके अन्य प्रमुख ब्रांडों में फोर स्क्वायर, रेड ऐंड व्हाइट, कवांडर, टिप्पर, नॉर्थ पोल आदि शामिल हैं।

सिमप्लस के अधिग्रहण से क्लाउड मार्ग पर बढ़ रही इन्फोसिस

देवाशिष महापात्र
बेंगलूरू, 11 फरवरी

सेल्सफोर्स सलाहकार कंपनी सिमप्लस का अधिग्रहण करने का इन्फोसिस का कदम उसके मौजूदा प्रबंधन द्वारा भावी विकास के क्षेत्रों में क्षमता बढ़ाने के लिए अकार्बनिक राह पर चलने वाले आक्रामक रुख को दर्शाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि संभवत: कंपनी ने कुछ बड़े आकार का अधिग्रहण करते हुए अपने अवरोधों को दरकिनार किया है।

बेंगलूरू मुख्यालय वाली इस कंपनी ने सोमवार देर रात अमेरिका स्थित मुख्यालय वाली कंपनी सिमपल्स का 25 करोड़ डॉलर में अधिग्रहण करने की घोषणा की थी। इससे तेजी से बढ़ते क्लाउड खंड में इसकी क्षमता में इजाफा होने की उम्मीद है। लोडस्टोन के बाद यह कंपनी द्वारा किया गया दूसरा सबसे बड़ा अधिग्रहण भी है जिसे इसने वर्ष 2012 में 35 करोड़ डॉलर में हासिल किया था।

आईटी आउटसोर्सिंग सलाहकार और पारीख कंसल्टिंग के संस्थापक पारीख जैन ने कहा कि जब उद्यम तेजी से क्लाउड को ओर जा रहे हों तो इन्फोसिस द्वारा सिम्प्लस का अधिग्रहण यह दर्शाता है कि वह क्लाउड जैसे अधिक विकास वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। एक्सेंचर और कॉग्निजेंट जैसी वैश्विक कंपनियां भी क्लाउड में भारी निवेश कर रही हैं।

प्रवासी निवेशकों की नजर अधिक लाभांश कर पर

ऐश्ली कुटिन्हो
मुंबई, 11 फरवरी

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के जरिये आने वाले और संधि का फायदा न उठाने वाले प्रवासी निवेशकों की चिंता बढ़ गई है क्योंकि लागू कर दरों के मुकाबले लाभांश पर विदहोल्डिंग कर अधिक होने के कारण उन्हें अधिक कर का भुगतान करना पड़ सकता है।

आयकर अधिनियम की धारा 115ए में संशोधन के बाद प्रावधान किया गया है कि प्रवासी निवेशकों के लाभांश पर 20 फीसदी कराधान, उपकर और अधिभार देय होगा। टीडीएस अथवा विदहोल्डिंग कर धारा 195 से प्रशासित है जिसके लिए दरों का उल्लेख वित्त अधिनियम की पहली अनुसूची के भाग दो में हर साल किया जाता है। आमतौर पर टीडीएस और अंतिम कर की दर समान होती है।

हालांकि पहली अनुसूची में संशोधन होना अभी बाकी है। जो प्रवासी निवेशक दोहरे कराधान से बचाव के समझौते के तहत राहत पाने के लिए योग्य नहीं हैं, उनके लिए विदहोल्डिंग कर 30 फीसदी अथवा 40 फीसदी और उपकर एवं अधिभार हो सकता है जो इस बात पर निर्भर करेगा कि वह शेयरधारक कोई कॉरपोरेट उपक्रम है अथवा गैर-कॉरपोरेट।

दूसरी ओर, घरेलू कर कानून के तहत इस प्रकार के विदेशी शेयरधारकों की आय के लिए कराधान 20 फीसदी कर के साथ उपकर एवं अधिभार का प्रावधान है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस विसंगति की मुख्य वजह मौजूदा कर कानून का ढांचा है जिसे दुरुस्त करने की आवश्यकता है।

नांगिया एंडर्सन के पार्टनर सुनील गिडवानी ने कहा, 'यदि इस प्रकार के लाभांश पर संधि का लाभ न मिले तो इस पर विदहोल्डिंग कर देय होगा जिसकी दरें अधिक हैं जो गैर-कंपनियों के लिए 30 फीसदी और कंपनियों के लिए 40 फीसदी है।'

पीडब्ल्यूसी इंडिया के पार्टनर (वित्तीय सेवा) सुरेश स्वामी ने कहा, 'भारतीय कंपनियां आमतौर पर अपने काकलन में गड़बड़ी से बचने के लिए विदहोल्डिंग कर के लिए काफी परंपरावादी रुख अपनाती हैं। इसलिए वे अधिक दर पर कर की गणना करेंगे जबकि प्रवासी की अंतिम कर देयता कम है। इससे उनका नकदी प्रवाह प्रभावित होगा।'

विशेषज्ञों का कहना है कि इस विसंगति के कारण एफपीआई के इतर अन्य विदेशी शेयरधारकों को भारत में आय के लिए रिटर्न दाखिल करना होगा और उसके बाद अधिक भुगतान के लिए वे रिफंड का दावा कर सकते हैं। यह कर अनुपालन लागत और समय के मुकाबले लाभांश प्राप्तियों पर निर्भर करेगा। लेकिन टीडीएस के मामले में ऐसा नहीं होता जिसके लिए 20 फीसदी दर निर्धारित है।

ईवाई इंडिया के पार्टनर सुब्रमण्यन कृष्णन ने कहा, 'विदेशी शेयरधारक को भारत में आयकर रिटर्न दाखिल करने और अतिरिक्त जमा कर के लिए दावा करने की जरूरत हो सकती है। आय की अंतिम कर देयता के साथ विदहोल्डिंग कर प्रावधान को संबद्ध करना विदेशी शेयरधारकों के लिए ऐच्छिक होगा।'

अधिक कर बोझ

- **यदि प्रवासी शेयरधारक डीटीएए लाभ के लिए पात्र नहीं होंगे तो उन पर 30 से 40 फीसदी विदहोल्डिंग कर लागू हो सकता है**
- **आयकर अधिनियम की धारा 115ए के तहत प्रवासी निवेशकों के लिए लाभांश कर 20 फीसदी है**

- **धारा 195 के तहत विदहोल्डिंग कर की दरें दी गई हैं जिसे संशोधित करना अभी बाकी है**
- **भारतीय कंपनियां विदहोल्डिंग कर के मामले में आमतौर पर परंपरावादी हैं**
- **एफपीआई के इतर विदेशी शेयरधारकों को आयकर रिटर्न दाखिल करना पड़ेगा**

आकर्षक बनी डिपॉजिटरी रिसीट

डिपॉजिटरी रिसीट (डीआर) के धारकों को लाभांश पर कम कर लगेगा, इसे पहले से ही पूंजीगत लाभ से छूट मिली हुई है

ऐश्ली कुटिन्हो
मुंबई, 11 फरवरी

ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट (डीआर) विदेशी निवेशकों के लिए और आकर्षक बन सकती है, जो सीधे तौर पर भारतीय इक्विटी में निवेश करते हैं क्योंकि बजट में कर आर्बिट्रेज का विस्तार किया गया है।

विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों को मिलने वाले लाभांश पर कर की दर अब 20 फीसदी है और इस पर अधिभार व उपकर लगता है। दूसरी ओर डिपॉजिटरी रिसीट के धारकों को दिए जाने वाले लाभांश पर कराधान की दर 10 फीसदी है।

साथ ही अमेरिकी डिपॉजिटरी रिसीट व जीडीआर में निवेश करने वालों पर पूंजीगत लाभ कर नहीं लगता, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि वे इन रिसीट्स को इक्विटी शेयर में तब्दील न करे। इसकी वजह यह है कि डिपॉजिटरी रिसीट्स भारतीय कंपनियों के शेयरों का प्रतिनिधित्व करती है और इन्हें विदेशी प्रतिभूतियां माना जाता है, जिस पर भारत में कोई कर नहीं लगता। सीधे तौर पर भारतीय शेयर में निवेश करने वाले निवेशकों को लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ पर 10 फीसदी और अल्पावधि वाले फायदे पर 15 फीसदी कर देना होता है।

पीडब्ल्यूसी के पार्टनर (वित्तीय सेवा) सुरेश स्वामी ने कहा, अब एडीआर, जीडीआर की लोकप्रियता बढ़ेगी क्योंकि यह विदेशी निवेशकों को भारतीय इक्विटी में सीधे निवेश के मुकाबले आकर्षक कर व्यवस्था की पेशकश करते हैं। यहां तक कि नियामकीय व्यवस्था में भी हाल में सकारात्मक बदलाव हुआ है। एडीआर, जीडीआर पर अर्जित लाभ पर भारत में कर नहीं लगता। साथ ही लाभांश पर कर भी 10 फीसदी है, जो आकर्षक है, लेकिन इस पर अधिभार व उपकर लगता है।

मौजूदा नियमों के तहत सिर्फ सूचीबद्ध कंपनियां ही डिपॉजिटरी रिसीट जारी कर सकती हैं। हाल में असूचीबद्ध कंपनियों को भी देश व विदेश में एक साथ सूचीबद्ध कराने की अनुमति दी गई है। अभी 32 कंपनियों के डिपॉजिटरी रिसीट दुनिया के अलग-अलग एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हैं। इनमें एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोसिस, विप्रो, वेदांत और टाटा स्टील शामिल हैं। इनमें से 17 डिपॉजिटरी रिसीट्स ने अपनी कीमतों में पिछले साल गिरावट देखी है जबकि 12 ने बढ़ोतरी दर्ज की है।

नांगिया एंडरसन के पार्टनर सुनील गिडवानी ने कहा, अभी पूंजीगत लाभ के नजरिये से एडीआर को इक्विटी शेयर पर बढ़त मिली हुई है। आगे एडीआर के लाभांश पर 10 फीसदी कर निवेशकों को अतिरिक्त फायदा पहुंचाएगा, खास तौर से उन लोगों को जो संधि वाली दरों के पात्र नहीं हैं।

ज्यादा एडीआर पहले ही अपने शेयरों के मुकाबले प्रीमियम पर कारोबार कर रहे हैं। विदेशी बाजार में बेहतर मूल्यांकन इसे उन कंपनियों के लिए आकर्षक बनाता है, जो विदेश से रकम जुटाना चाहती हैं। विगत में एचडीएफसी बैंक ने एडीआर बाजार से रकम जुटाए हैं।

विशेषज्ञों का हालांकि मानना है कि ऐसा शायद ही होगा कि डिपॉजिटरी रिसीट्स नहीं जारी करने वाली कंपनियां इस विकल्प को सिर्फ विदेशी शेयरधारकों के फायदे के लिहाज से चुनेंगी।

गिडवानी ने कहा, नियामक हालांकि प्रायोजित डिपॉजिटरी रिसीट्स की अनुमति देता है, लेकिन पूरी प्रक्रिया से लागत और स्थानीय व विदेशी नियामक की मंजूरी जुड़ी हुई है।

विदेशी निवेशकों के लिए फायदेमंद

- नियामकीय व्यवस्था में भी हाल में सकारात्मक बदलाव हुआ है। एडीआर, जीडीआर पर अर्जित लाभ पर भारत में कर नहीं लगता
- जीडीआर की लोकप्रियता बढ़ेगी क्योंकि यह विदेशी निवेशकों को भारतीय इक्विटी में सीधे निवेश के मुकाबले आकर्षक कर व्यवस्था की पेशकश करते हैं

ज्यादा प्रावधान से इलाहाबाद बैंक को 1,986 करोड़ रुपये का नुकसान

नम्रता आचार्य
कोलकाता, 11 फरवरी

कृषि कर्ज पर ज्यादा प्रावधान के कारण इलाहाबाद बैंक का नुकसान तीसरी तिमाही में 1,986 करोड़ रुपये पर पहुंच गया, जो पिछले साल की समान अवधि में 733 करोड़ रुपये रहा था। आरबीआई ने बैंक से पुनर्गठित कृषि कर्ज पर दोबारा नजर डालने को कहा था, जिसके कारण इस क्षेत्र में ज्यादा एनपीए की पहचान हुई। बैंक पिछली दो तिमाही से इसमें जुटी हुई है। बैंक के कार्यकारी निदेशक के रामचंद्रन ने यह जानकारी दी।

उन्होंने कहा, हमने शाखाओं में कृषि कर्ज से जुड़े खातों का अध्ययन किया है। हमें जहां भी लगा, हमने एनपीए के तौर पर उसकी पहचान की। तीसरी तिमाही में कृषि एनपीए 2,500 करोड़ रुपये था। एनपीए के लिए बैंक का प्रावधान तीसरी तिमाही में 3,002 करोड़ रुपये रहा। बैंक का परिचालन लाभ दिसंबर तिमाही में 897.66 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल की समान अवधि में 768.96 करोड़ रुपये रहा था। कुल उधारी के प्रतिशत के तौर पर सकल एनपीए 18.93 फीसदी रहा, वहीं शुद्ध एनपीए 5.13 फीसदी रहा।

सिंडिकेट बैंक का लाभ बढ़ा

फंसे कर्ज में कमी से सिंडिकेट बैंक के शुद्ध लाभ में दिसंबर 2019 तिमाही में काफी वृद्धि हुई है। चालू वित्त वर्ष की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में बैंक का शुद्ध लाभ 434.82 करोड़ रुपये रहा। 2018-19 की इसी तिमाही में उसे 107.99 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था। बैंक ने बताया कि समीक्षाधीन अवधि में उसकी कुल आय बढ़कर 6,316.57 करोड़ रुपये रही। *भाषा*

आईडीबीआई बैंक का कर पूर्व लाभ 755 करोड़ रुपये

आईडीबीआई बैंक का कर पूर्व लाभ दिसंबर तिमाही में 755.89 करोड़ रुपये रहा, जिसे शुद्ध ब्याज आय में बढ़ोतरी और फंसे कर्ज के लिए प्रावधान में कमी का सहारा मिला। पिछले साल की समान अवधि में बैंक का कर पूर्व नुकसान 5,805 करोड़ रुपये रहा था।

बैंक का शुद्ध नुकसान 5,763 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल की समान अवधि में 4,185 करोड़ रुपये रहा था। बैंक ने कर की कम दर का विकल्प चुना और तीसरी तिमाही में 6,273 करोड़ रुपये का एकमुश्त झटका झेला। बैंक का शेयर आज बीएसई पर 2.1 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ 35 रुपये पर बंद हुआ। एलआईसी की सहायक आईडीबीआई बैंक कमजोर परिसंपत्ति गुणवत्ता और लाभ के कारण अभी आरबीआई के त्वरित उपचारात्मक कार्रवाई के दायरे में है। मौजूदा वित्त वर्ष में बैंक को इस दायरे से बाहर निकलने की उम्मीद है। *बीएस*

संक्षेप में

5 साल में इनविट से जुटाए जाएंगे 2 लाख करोड़ रुपये

रेटिंग एजेंसी इक्रा ने मंगलवार को कहा कि इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (इनविट) पर केंद्र सरकार ने जोर दिया है, जिसमें अगले पांच साल में अनुमानित तौर पर 2 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा जुटाने की क्षमता है। इक्रा के अध्ययन के मुताबिक, अगले पांच साल में अनुमानित तौर पर 2 लाख करोड़ रुपये जुटाए जा सकते हैं, जिनमें अगले वित्त वर्ष का 80,000 करोड़ रुपये शामिल है। सड़क, दूरसंचार फाइबर, बिजली पारेषण व उत्पादन क्षेत्र की परिसंपत्तियां इसके दायरे में आ सकती हैं। सबसे ज्यादा नजर एनएचएआई के इनविट पर है। *बीएस*

एनएसई ने 2019 में जोड़े 30 लाख नए निवेशक

नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ने साल 2019 में 30 लाख नए क्लाइंट जोड़े, जो इससे एक साल पहले के मुकाबले 4.5 फीसदी की बढ़ोतरी दर्शाता है। यह बढ़ोतरी हालांकि पांच साल की सालाना बढ़ोतरी 11 फीसदी से कम है। बाजार में उतारचढ़ाव का नए निवेशक जुड़ने पर असर पड़ा होगा। पिछले साल निफ्टी-50, 12 फीसदी चढ़ा जबकि व्यापक बाजार निफ्टी मिडकैप 100 और निफ्टी स्मॉलकैप 100 में क्रमश: 4.3 फीसदी और 9.5 फीसदी की गिरावट दर्ज हुई। एनएसई के प्रबंध निदेशक व सीईओ विक्रम लिमये ने कहा, अगले तीन साल में 5 करोड़ निवेशक होंगे। अभी एक्सचेंज पर करीब 3 करोड़ क्लाइंट हैं। *बीएस*

कतर इन्वेस्टमेंट ने पूरा किया अदाणी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई सौदा

अदाणी टांसमिशन लिमिटेड ने आज ऐलान किया कि कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने अदाणी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड की 25.10 फीसदी हिस्सेदारी के अधिग्रहण का काम पूरा कर लिया है। अदाणी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड में कतर इन्वेस्टमेंट का कुल निवेश 3,220 करोड़ रुपये है, जिसमें 1,210 करोड़ रुपये की इक्विटी और शेयरधारक का करीब 2,010 करोड़ रुपये का कर्ज शामिल है।

इस सौदे पर 11 दिसंबर 2019 को हस्ताक्षर किए गए थे और उसके बाद सभी आवश्यक मंजूरी हासिल की गई।

अदाणी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड ने हाल में निवेश श्रेणी वाला 1 अरब डॉलर का बॉन्ड जारी किया है, जो निजी क्षेत्र की भारतीय यूटिलिटी की तरफ से पहला बॉन्ड है। इस इश्यू को अंतरराष्ट्रीय निवेशकों का काफी ज्यादा समर्थन मिला और 5.9 गुना से ज्यादा आवेदन मिले। अदाणी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड की 25.1 फीसदी हिस्सेदारी बिक्री से मिलने वाली रकम का इस्तेमाल अदाणी ट्रांसमिशन लिमिटेड ने 1,209.62 करोड़ रुपये के परपेचुअल बॉन्ड की वापसी में किया। 1,209.62 करोड़ रुपये की वापसी के बाद प्रवर्तक का बकाया परपेचुअल घटकर 2,544.38 करोड़ रुपये रह गया। *बीएस*

एनएसई को सेबी का नोटिस

समी मोडक
मुंबई, 11 फरवरी

बाजार नियामक सेबी ने आनंद सुब्रमण्यन की नियुक्ति और पदोन्नति पर नैशनल स्टॉक एक्सचेंज को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नियामक ने सबसे पहले अक्टूबर 2019 में नोटिस जारी किया था और उसके बाद दिसंबर 2019 में पूरक नोटिस जारी किया गया।

सुब्रमण्यन अप्रैल 2013 में एनएसई से मुख्य रणनीतिक अधिकारी के तौर पर जुड़े थे और तभी चित्रा रामकृष्णन ने प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्याधिकारी का पद संभाला था। अप्रैल 2015 में उन्हें पदोन्नत कर समूह का मुख्य परिचालन अधिकारी बनाया गया। सुब्रमण्यन की नियुक्ति और वेतन पैकेज हैरान करने वाला था, खास तौर से इसलिए क्योंकि उनका पिछला प्रोफाइल एक लॉजिस्टिक्स फर्म के साथ जुड़ा था। इस मामले में एनएसई ने सेबी से कुछ निश्चित दस्तावेज जांच के लिए मांगा है। इसके निपटान के लिए सहमति आवेदन भी जमा कराया गया है। इस व्यवस्था के तहत कथित गड़बड़ी का निपटान गलती स्वीकार करने या उसके बिना हो सकता है। सेबी का नोटिस सुब्रमण्यन के पद छोड़ने के तीन साल बाद आया है। इसके अलावा सेबी ने एनएसई को कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस (कैम्स) की हिस्सेदारी एक साल के भीतर बेचने को कहा है।

फिनटेक में उबर ने मजबूत किए कदम

पीरजादा अबरार
बेंगलूरु, 11 फरवरी

टैक्सी सेवा की दिग्गज कंपनी उबर ने आज उबर मनी के गठन की घोषणा की जो 100 से अधिक प्रौद्योगिकी पेशेवरों की टीम होगी। इनके पास कंपनी के हैदराबाद टेक सेंटर में वैश्विक वित्तीय उत्पादों और तकनीकी नवाचारों की जिम्मेदारी होगी। एशिया प्रशांत क्षेत्र में यह अपनी तरह की प्रथम पहल है। हैदराबाद के अलावा उबर मनी टीम की मौजूदगी इसके सैन फ्रांसिस्को, पालो अल्टो, न्यूयॉर्क और एम्सटर्डम स्थित टेक केंद्रों में भी है।

हैदराबाद स्थित टीम आने वाले समय के नए वैश्विक फीचरों और सुधारों को लागू करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इसमें रियल-टाइम की कमाई, अद्यतन डेबिट खातों, उबर ड्राइवरों के लिए डेबिट कार्ड के साथ साथ उबर वॉलेट और उबर सवारों के लिए उबर क्रेडिट कार्ड शामिल है। कंपनी ने कहा कि फ्रंट एंड, फुल-स्टैक, मोबाइल, मशीन लर्निंग और डेटा इंजीनियरिंग की गहरी समझ के साथ उबर मनी टीम भुगतान के नए तरीकों को लागू करने, वित्त अनुपालन उपकरणों को सक्षम बनाने और उसे तैयार करने पर ध्यान देगी। इंजीनियरिंग निदेशक नागा कासु ने कहा, 'उबर हैदराबाद टेक सेंटर के पास जोखिम, भुगतान, वित्त रिपोर्टिंग और एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म इंजीनियरिंग में सर्वश्रेष्ठ स्तरीय फिनटेक कौशल है।' उन्होंने कहा, 'हम हैदराबाद को उबर के लिए पूरी तरह से स्पेक्ट्रम टेक साइट में बदलने के लिए इंजीनियरिंग के अलावा बढ़ते और ऊपर उठते डेटा विज्ञान, एनालिटिक्स और उत्पाद प्रबंधन संगठनों में गुंजाइश तलाश रहे हैं।'

भारतीय फिनटेक बाजार में समग्र लेनदेन मूल्य 2019 के करीब 66.1 अरब डॉलर से उछलकर 2023 में 137.8 अरब डॉलर होना अनुमानित है। पीडब्ल्यूसी और उद्योग निकाय एसोचैम की एक रिपोर्ट के मुताबिक इसमें 20.18 फीसदी की सालाना चक्रवृद्धि दर से वृद्धि हो रही है। उभरते बाजार इसमें अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। ईवाई की ग्लोबल फिनटेक एडॉप्शन इंडेक्स 2019 के मुताबिक 2019 में चीन और भारत दोनों का फिनटेक अपनाने की दर 87 फीसदी रही जो 64 फीसदी की वैश्विक औसत दर से काफी अधिक है।

2 दिन के दौरे पर भारत आएंगे ट्रंप

शुभायन चक्रवर्ती
नई दिल्ली, 11 फरवरी

अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप पहली बार भारत आ रहे हैं। 24 फरवरी से शुरू हो रही दो दिवसीय यात्रा के दौरान वह नई दिल्ली और अहमदाबाद में रहेंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां अमेरिका से इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वीपन सिस्टम खरीदने के सौदे पर हस्ताक्षर के माध्यम से रक्षा संबंध मजबूत करेंगे, वहीं भारत की नजर अमेरिका के साथ अन्य कारोबारी समझौतों पर बनी रहेगी, जो भारत का सबसे बड़ा निर्यात केंद्र है। अधिकारियों ने कहा कि अमेरिका के कृषि उत्पादों पर शुल्क कम करके और मेडिकल उपकरणों पर छूट का आश्वासन देकर संबंध मजबूत करना चाहता है।

सोमवार की रात को व्हाइट हाउस द्वारा जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि ट्रंप अपनी पत्नी मेलिना के साथ अहमदाबाद जाएंगे। अहमदाबाद प्रधानमंत्री मोदी का गृह राज्य और महात्मा गांधी की जिंदगी और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाने के कारण खास है।

विदेश नीति पर ट्रंप अपने पूर्ववर्ती की नीति पर चल रहे हैं और वह भारत प्रशांत क्षेत्र में भारत के साथ रणनीतिक साझेदार बनने को इच्छुक हैं, जिससे चीन के इस इलाके में बढ़ते प्रभाव पर काबू पाया जा सके। इसके अलावा ईरान के चाबहार बंदरगाह को लेकर कुछ ढील देने पर भी विचार कर सकते हैं। लेकिन परंपराओं से इतर उन्होंने व्यापार नीति को लेकर भारत के खिलाफ हमले किए और आयात शुल्क में बढ़ोतरी कर दी। 2019 में ट्रंप ने भारत को टैरिफ किंग कहना शुरू किया और शिकायत की कि हार्ली डेविडसन मोटरसाइकिलों पर भारी कर लगाया जाता है।

मोदी ने अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान ट्रंप से मामले का समाधान करने और शुल्क घटाने की अपील की थी, वहीं ट्रंप ने भारत के साथ बहुत जल्द कारोबारी समझौता करने का वादा किया था।

पिछले 4 साल के दौरान भारत से अमेरिका को होने वाले निर्यात में बढ़ोतरी हुई है और 2017-18 के 47.8 अरब डॉलर की तुलना में 2018-19 में यह बढ़कर 52.3 अरब डॉलर हो गया। वहीं दूसरी तरफ आयात भी बढ़ा है और वित्त वर्ष 18 के 26.6 अरब डॉलर से बढ़कर यह 35.5 अरब डॉलर हो गया।

दोनों देश जहां समग्र व्यापार पैकेज पर काम कर रहे हैं, वहीं अमेरिकी वाणिज्य अधिकारियों ने अतिरिक्त उपकर लगाकर मेडिकल उपकरणों के आयात पर लगाम लगाने की भारत की कवायद पर नाखुशी जाहिर की है। भारत ने कहा है कि वह कर वापस नहीं लेगा, लेकिन सूत्रों ने कहा कि सरकार अभी भी कुछ खास महंगे उपकरण जैसे कोरोनरी स्टेंट के लिए व्यापार मुनाफा नीति को अनुमति देने पर विचार कर रही है।

एक अधिकारी ने कहा, 'औद्योगिक उत्पादों, इंजीनियरिंग उत्पादों और सूचना तकनीक से जुड़े सामान जैसे स्मार्ट घड़ियों और आई फोन पर शुल्क करने जैसी अन्य अमेरिकी मागें बहुत भारी भरकम हैं और ट्रंप के दौरे के दौरान इस मसले के समाधान की कोई उम्मीद नहीं है।'

भारत की ओर से कृषि उत्पादों पर ज्यादा कर लगाए जाने से 24 करोड़ डॉलर अतिरिक्त कर मिलने का अनुमान लगाया गया था। भारत ने कहा था कि उसने मई 2018 में अमेरिका द्वारा स्टील पर 25 प्रतिशत और एल्युमीनियम उत्पादों पर 10 प्रतिशत कर लगाने के कारण यह कर लगाया है। वहीं अमेरिका ने अपने कदम पीछे खींचने के भी संकेत दिए थे। अमेरिका की ओर से लगाया गया कर भारत केंद्रित नहीं है, लेकिन उसने बार बार यह कहा है कि भारत से होने वाले आयात पर चीनी उत्पादों की तर्ज पर कर लगाया जा सकता है।

24 फरवरी को भारत पहुंचेंगे ट्रंप

- अपनी पत्नी मेलिना के साथ पहली बार भारत आ रहे ट्रंप दिल्ली और अहमदाबाद जाएंगे
- मेडिकल उपकरणों पर उपकर लगाए जाने से नाराज है अमेरिका
- अमेरिका से आने वाले कृषि उत्पादों पर कर में छूट की पेशकश कर सकता है भारत

दवा की श्रेणी में आएंगे सभी मेडिकल उपकरण

सोहिनी दास
मुंबई, 11 फरवरी

आगामी 1 अप्रैल से भारत में बिकने वाले सभी मेडिकल उपकरण दवा की श्रेणी में माने जाएंगे और इनका नियमन औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम 1940 के तहत होगा। इस सिलसिले में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने मंगलवार को अधिसूचना जारी की है।

सरकार का फैसला

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि दवाओं से जुड़े तकनीकी मसलों पर फैसला करने वाले औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड (डीटीएबी) से सलाह के बाद मंत्रालय ने 1 अप्रैल से सभी मेडिकल उपकरणों को दवा के रूप में वर्गीकृत करने का फैसला किया है।

इनमें मनुष्यों व जानवरों के लिए इस्तेमाल होने वाले अपरेटस, अप्लायंसेज, इंप्लांट्स, इंस्ट्रूमेंट्स (सॉफ्टवेयर या एसेसरी सहित) सहित सभी उपकरण शामिल होंगे।

इस समय 23 मेडिकल उपकरणों को दवा के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इनमें कार्डियक स्टेंट्स, ड्रग इलूटिंग कार्डियक स्टेंट्स, कंडोम, इंट्रा यूरीन डिवाइस सहित कुछ उपकरणों को ही मूल्य नियंत्रण के दायरे में लाया गया है और ये आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची (एनएलईएम) में शामिल हैं।

उद्योग लॉबी ने कहा कि इस तरह का कोई औपचारिक आश्वासन नहीं दिया गया है कि नीति आयोग के साथ मिलकर स्वास्थ्य मंत्रालय मसौदा मेडिकल उपकरण विधेयक पर काम करेगा। मेडिकल उपकरण लॉबी समूह के एक वरिष्ठ सदस्य ने कहा, 'मेडिकल उपकरणों को दवाओं के रूप में नहीं माना जा सकता है। इसके लिए अलग नियामकीय ढांचे की जरूरत है। यह केवल अस्थायी व्यवस्था हो सकती है।'

दिसंबर में सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग ने सभी मेडिकल उपकरणों को चरणबद्ध तरीके से एक नियामकीय ढांचे में लाने और अलग मेडिकल उपकरण प्रशासन (एमडीए) का प्रस्ताव किया था।

बीएस बातचीत

तमाम क्षेत्रों की फंसी हुईं परियोजनाएं बैंकों की बड़ी चिंता

पूर्वी भारत के सबसे पुराने बैंकों में से एक यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया का विलय ओरिएंटल बैंक आफ कॉमर्स और पंजाब नैशनल बैंक के साथ 1 अप्रैल 2020 से होने वाला है। विलय के पहले यूबीआई के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्याधिकारी **अशोक कुमार प्रधान** ने **नम्रता आचार्य** और **ईशिता आयान दत्त** से बातचीत में बैंकिंग क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं पर बात की। प्रमुख अंश...

सरकारी बैंकों पर बजट के असर के बारे में आपका क्या आकलन है?
बैंकर के रूप में मुझे लगता है कि जमा बीमा की सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपये किया जाना सकारात्मक है, लेकिन इसका असर बैंकों के परिचालन लाभ पर पड़ेगा। बैंकों के पुनर्पूंजीकरण के बारे में सरकार ने आश्वस्त किया है कि जब भी जरूरत होगी, बैंकों को पूंजी मुहैया कराई जाएगी। यह अनुमान है कि बैंक बाजार से धन जुटाएंगे, लेकिन उनकी बैलेंस शीट देखकर लगता है कि संभवत: वे बाजार में जाने में सक्षम नहीं होंगे और वे कुल मिलाकर बेहतर माहौल होने पर कर्ज देने के मामले में उम्मीद कर सकते हैं।

विलय में क्या प्रगति है?
विलय का काम आराम से चल रहा है। सभी 34 समितियों ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इसका मूल्यांकन सलाहकार द्वारा किया जाना है। वे तीनों बैंकों के संयुक्त विचारों के मानकीकरण को लेकर बेहतर स्थिति में होंगे।

स्वैप रेशियो पर फैसला हो गया है?
मूल्यांकन का काम हो चुका है और संधि की प्रक्रिया चल रही है।

बैंकों की समितियों की प्रमुख सिफारिशें क्या हैं?
सभी बैंक भारत सरकार से दिशानिर्देश पाते हैं। इसलिए ढांचा एकसमान होगा। इसमें उत्पादों के फीचर के कोड तैयार करने और तालमेल तथा एकीकृत इकाई को स्पष्टता देने का मसला है।

आईटी के विलय की क्या स्थिति है?
प्रमुख बैंक इन्फोसिस से बात कर रहा है। हमारे जीएम, आटी भी उनके साथ सहयोग कर रहे हैं। इन्फोसिस बैंक आफ बड़ौदा के विलय पर काम कर रही है। उम्मीद है कि वे बैंक आफ बड़ौदा के लिए कुछ समाधान निकाल लेंगे। अगर उन्हें ठीक ठाक सफलता मिलती है तो इसे आगे बढ़ाया जाएगा। उसके बाद हमारे मामले में यह आसान होगा।

विलय की लागत क्या होगी?
तत्काल तो आईटी के एकीकरण की लागत आनी है। शेष दिखाई न देने वाली लागत है। एक साल या उसके बाद ही वास्तविक तस्वीर सामने आएगी। उसके बाद प्रशासनिक लागत के हिसाब से बहुत ज्यादा बचत होगी। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली में अगल-बगल की शाखाओं को तार्किक बनाया जा सकता है। ओबीसी और पीएनबी की तमाम इलाकों में उपस्थिति है। उसके नजदीक हमें शाखाओं की जरूरत नहीं होगी, बल्कि कुछ का विलय किया जा सकता है, जिससे लाइसेंस खाली हो जाएगा और हम अन्य इलाकों में शाखाएं खोलने में सक्षम हो सकेंगे।

कर्ज देने में बढ़ोतरी करने के लिए पिछली मौद्रिक नीति में उठाए गए कदमों पर आपकी क्या राय है?
मुझे लगता है कि वह एक शानदार मौद्रिक नीति थी। निश्चित रूप से कर्ज देने को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिलेगा।

क्या कृषि ऋण चिंता का विषय है?
कृषि ऋण चिंता का विषय है। इसे अनंतकाल के कर्ज के रूप में देखा जाता है। अब नियामक सुझाव दे रहे हैं कि इसे खत्म किया जाना चाहिए और नए सिरे से कर्ज दिया जाना चाहिए। हमने सुझाव दिया है कि कर्ज का एक हिस्सा जारी रखा जाए और शेष को बंद किया जाना चाहिए।

मौजूदा परिदृश्य में बैंकों की सबसे बड़ी चिंता क्या है?
अटकी हुई परियोजनाएं बैंकरों की चिंता की प्रमुख वजह हैं। हमें इस समस्या का समाधान निकालने की जरूरत है। बिजली उद्योग का ही 2 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा फंसा हुआ है। अगर बिजली क्षेत्र का समाधान निकल जाए तो एक मोटी राशि खाली हो जाएगी।

कर्ज बांटने की स्थिति कैसी रही है?
इस वित्त वर्ष में कर्ज देने की स्थिति खराब रही है, जो बैंकिंग क्षेत्र के लिए 7 से 7.5 प्रतिशत रही। यूबीआई में स्थिति तुलनात्मक रूप से बेहतर रही है। खुदरा में हमारी कर्ज की वृद्धि 14 प्रतिशत है। एमएसएमई में 7 से 8 प्रतिशत है।

चीन से सस्ता आयात रोकें

पृष्ठ 1 का शेष...

गुजरात में बल्क दवा बनाने वाली एक इकाई के मालिक ने कहा कि अगर सरकार देश में कच्चा माल बनाना चाहती है तो उसे चीन से सस्ते आयात को रोकने के लिए एंटी डंपिंग शुल्क लगाना होगा। चीनी आयात भारतीय उत्पादन की तुलना में करीब 30 फीसदी सस्ता होता है। भारतीय बल्क दवा उद्योग अब महंगे जटिल एपीआई उत्पाद बनाता है क्योंकि सख्त पर्यावरण कानूनों के कारण उन्हें अपनी क्षमताओं के विस्तार में दिक्कत आ रही थी।

इसके कारण सस्ते उत्पादों का चीन से आयात शुरू हुआ। वैश्विक जानकारों का भी कहना है कि चीन में कोरोनावायरस के संक्रमण के कारण पैदा हुए संकट से भारतीय उद्योग के पास एक बेहतरीन मौका है। अमेरिकी खाद्य एवं दवा विभाग के पूर्व प्रमुख स्कॉट गॉटलिब ने कुछ दिन पहले ट्वीट किया कि चीन से आपूर्ति बाधित हुई है और भारत को इस मौके का फायदा उठाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि भारत में करीब 1,500 संयंत्र एपीआई बना सकते हैं लेकिन वे अपनी क्षमता का 40 फीसदी ही उत्पादन कर रहे हैं। इसके लिए नियामकों को उद्योग के साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। दवा विभाग ने आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश और असम में चार बल्क दवा पार्क बनाने का प्रस्ताव रखा है।

बीएस सूडोकू 3662 | परिणाम संख्या 3661

5					2	3		8
					4	7		
8		2					4	
			8					5
	9		3	7	5		2	
4					1			
	3					8		9
		9	6					
2		4	9					7

8	6	9	3	2	4	7	5	1
7	5	3	1	6	8	2	4	9
1	4	2	5	7	9	3	8	6
6	2	1	8	5	7	4	9	3
4	8	7	9	3	6	5	1	2
9	3	5	4	1	2	6	7	8
2	7	4	6	9	1	8	3	5
3	9	6	7	8	5	1	2	4
5	1	8	2	4	3	9	6	7

कैसे खेलें?
हर रो, कॉलम और 3 बाई 3 के बॉक्स में एक से लेकर नौ तक की संख्या भरें।

मध्यम
★★★☆☆

क्षेत्रीय मंडियों के भाव

उत्तर प्रदेश | राजस्थान | पंजाब

कानपुर
गेहूं लूज 2020/2030, जौ 1760/1780, चावल मसूरी 2250/2300, चावल मोटा 2200/2250, सरसों 4150/4200, तिल सफेद 8900/9000, सोया (टीन) 1500/1525, तेल सरसों कच्ची घानी वैट पेड (टीन)1425/1525,

लखनऊ
गेहूं दड़ा 2020/2030, गेहूं शरबती 2825/2925, चावल शरबती सेला 3700/3750, स्टीम 4200/4250, लालमती 3150/3200, चावल (सोना) 2700/2750,

चंदौसी
(प्रति किलो): मैन्था ऑयल 1352, बोल्ड क्रिस्टल (12 नं.)1430, फ्लैक 1372, डीएमओ 985, टरपीन लैस बोल्ड 1445

मुजफ्फरनगर
गुड़ (40 किलो): लड्डू 1080/1150, खुरपा 980/1000,चाकू 1030/1100, रसकट 880/900, शक्कर 1150/1180, चीनी मिल डिली. (क्विं.) (जीएसटी अतिरिक्त): खतौली 3300, बुंदकी 3270, बुढ़ाना 3300, शामली 3250,

हापुड़
गुड़-चीनी: चीनी हाजिर 3500/3600, गुड़ (प्रति 40 किलो) बाल्टी 950/960, तिलहन: सरसों (42 प्रतिशत कंडी.) 4225, खल: सरसों 2150/2250, बिनौला 2250/2350, चना छिलका 2100/2150,

जयपुर
अनाज: चावल डीबी 5000/5200, गेहूं (मिल) 2120/2125, मक्की 2100/2115, बाजरा 1750/1760, जौ 1775/1800, ग्वार लूज 3725/3750, ज्वार कैटलफीड 2400/2500, तेल-तिलहन: सरसों(मिल पहुंच) 4200/4225,

श्रीगंगानगर
गेहूं (ढेरी) 2000/2100, ग्वार 3600/3650, जौ 2050/2060,

जोधपुर
गेहूं 2050/2100, जौ 1800/1825, पोपकोन मक्की 4400/4500, ग्वार डिलीवरी (ऑलपेड) 3900/3950, ग्वारगम 6900/7000, बाजरा (गुजरात) 1800/1825, बाजरा (जयपुर) 1800/1825, चना 4000/4100, काबली चना 4800/6000, मूंग 6900/7000,

खन्ना
जीएसटी अतिरिक्त (प्रति क्विं.): राइसब्रान (खाद्य)(प्रति प्वाइंट)108, राइसब्रान (अखाद्य) 105, खल सरसों 1870, डीओसी: राइसब्रान बेच सफेद 1100, लाल 1100, कंटीन्यूअस 1150,

लुधियाना
दाल-दलहन: राजमां चित्रा 8000/8700, अरहर दाल 7400/7900, उड़द साबुत 7300/8400, उड़द धोया 9000/9700, छिलका 8500/9200, दाल मसूर 5900/6200, चनादाल 5300/5400,

अमृतसर
चावल: बासमती (1121 नं.) स्टीम 5800/5900, सेला 5250/5300, शरबती साधारण सेला 3700/3750, शरबती स्टीम 4000/4050,चावल 1509 सेला 4950/5000, धान: शरबती 2050/2100,

बठिंडा
रुई (प्रति मन): जे-34 पंजाब 4010/4040, हरियाणा 3980/4000, राजस्थान 3950/3980, खल (प्रति क्विं.): बिनौला 2300/2400, सरसों खल 1900/2000,

फाजिल्का
गेहूं 2040/2050, सरसों 3975/4050 रुई (प्रति मन): (जे-34) 4050/4100, कपास देशी 4300/4400, कपास नरमा (क्विं.) 5050/5300, बिनौला (टैक्सपेड): खल 2200/2300,

जालंधर
गेहूं दड़ा 2030/2050, चावल परमल कच्चा 2325/2365, से ला 2260/2310, मक्की यूपी 2000/2025, दाल उड़द छिलका 8600/9700, चना देशी 4675/4725, दाल चना 5050/5125, काबली चना 5200/6100, राजमां चित्रा पुणे 7300/8700, चीन 8300/8700, शर्मिली 6000/7300,

करनाल
गेहूं दड़ा 2035/2045, बासमती चावल 6200/6300, धान 1121 नं. 2700/2750, पूसा 1509 धान 2600/2640, शरबती धान 2050/2100, सेला (1509 नं.) चावल 4950/4975, स्टीम 5800/5900,

हिसार
ग्वार 3700/3750, जौ 1840/1850, सरसों 3850/3900, मूंग 7000/7100, गेहूं 2050/2065,

जींद
जीएसटी अतिरिक्त: गेहूं 2100/2130, आटा (प्रति 44 किलो) 1040/1060, मैदा 1140/1160, देशी घी (एक ली/जार) 360/480, रिफाइंड (टीन) 1480/1500,

भिवानी
जीएसटी अतिरिक्त: सरसों 3850/3900, खल बिनौला मोटी 2150/2250, बिनौला 2600/3100, सरसों तेल 8500/8550, गेहूं 2000/2100, ग्वार 3700/3750, बाजरा 1700/1750

एनएनएस

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 12 अंक 307

आप की जीत

दिल्ली चुनावों के लिए अपने व्यस्त प्रचार अभियान के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बार-बार राजधानी के मतदाताओं से कहा कि वे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर 'कमल' का बटन इतनी जोर से दबाएं कि 'करंट' शाहीन बाग तक महसूस हो। शाहीन बाग में हजारों लोग नागरिकता संशोधन अधिनियम का विरोध कर रहे हैं। मंगलवार को आम आदमी पार्टी (आप) की जबरदस्त जीत के बाद यकीनन 'करंट' भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को महसूस हो रहा है। पार्टी ने अपने प्रचार अभियान में कई बार सीमा का उल्लंघन किया लेकिन वह जीत हासिल करने में नाकाम रही। हालांकि उसके मत प्रतिशत में 6 फीसदी का सुधार हुआ। इस बीच दिल्ली पर सन 2013 तक 15 वर्ष शासन करने वाली कांग्रेस 5 फीसदी से भी कम मत प्रतिशत के साथ और अधिक अप्रासंगिक हो गई।

चुनाव परिणाम कई एक्जिट और ओपिनियन पोल के अनुरूप ही रहे लेकिन ये नतीजे एक बार फिर इस बात का मजबूत संकेत देते हैं कि मतदाता स्थानीय और राष्ट्रीय चुनाव में साफ अंतर कर रहे हैं। विधानसभा चुनावों में स्थानीय मुद्दे अभी भी अहम हैं। यह बात आप के चुनाव प्रचार से साबित होती है जो पूरी तरह बीते पांच वर्ष के विकास कार्यों के इर्दगिर्द केंद्रित रहा। खासतौर पर शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए गए काम।

एक सीमा तक बिजली और पानी नि:शुल्क देने और महिलाओं के लिए नि:शुल्क बस यात्रा ने भी आप को फायदा पहुंचाया। हालांकि सब्सिडी आधारित शासन का मॉडल आगे बढ़ने का यह सही तरीका नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राजनीति को शासन के मुद्दों तक सीमित रखा और चतुराईपूर्वक हनुमान मंदिर गए। भाजपा का प्रचार अभियान भावनात्मक और असंगत नारेबाजी तक सीमित था।

पार्टी ने केजरीवाल पर हमला करते हुए उन्हें 'आतंकवादी' तक कह दिया। एक केंद्रीय मंत्री पार्टी कार्यकर्ताओं से 'गद्दारों' को गोली मारने के नारे लगवाते दिखे, एक अन्य भाजपा सांसद ने प्रदर्शनकारियों की तुलना आतंकवादियों और लुटेरों से की। कुल मिलाकर देखें तो हाल के समय में राज्य दर राज्य विधानसभा चुनावों के नतीजे दिखाते हैं कि राष्ट्रवादी विचार को आगे बढ़ाना भाजपा के काम नहीं आया। बिहार में जहां इस वर्ष के अंत में चुनाव होने हैं, वहां पार्टी बेहतर स्थिति में नजर आ रही है लेकिन पार्टी की असली परीक्षा पश्चिम बंगाल में होगी जहां उसे एक मजबूत सत्ताधारी क्षेत्रीय दल का मुकाबला करना है। वहां भी पार्टी के पास मजबूत स्थानीय नेतृत्व नहीं है और ध्रुवीकरण की आशंका बहुत अधिक है।

दिल्ली के चुनाव में जहां भाजपा के लिए सबक हैं, वहीं सबसे बड़ी पराजय कांग्रेस की हुई है। पार्टी लगातार दूसरे चुनाव में अपना खाता खोलने में नाकाम रही। उसके मत प्रतिशत में और अधिक कमी आई। कांग्रेस के ज्यादातर प्रत्याशी अपनी जमानत तक नहीं बचा पाए। यह बात इस पुराने राजनीतिक दल के पराभव की कहानी स्वयं कहती है।

भाजपा की पराजय कांग्रेस के लिए सांत्वना नहीं हो सकती है क्योंकि कुछ वर्ष पहले तक यहां पार्टी का जबरदस्त जनाधार था। कांग्रेस की हार का दोष उसके शीर्ष नेतृत्व का है। पार्टी को अपने नेतृत्व का मुद्दा जल्द ही हल करना होगा तभी वह चुनावी राजनीति में प्रासंगिक रह सकेगी। जब तक कांग्रेस खुद को नए सिरे से खड़ा नहीं करती और अन्य विपक्षी दलों के साथ मिलकर प्रतिपक्षी बहस नहीं खड़ी करती, भाजपा देश में चुनावी राजनीति की धुरी बनी रहेगी।

अजय मोहंती

घरेलू समस्याओं का हो रहा वैश्विक प्रभाव

अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर और सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में देश जिन हालात से गुजर रहा है उनका असर मित्र राष्ट्रों तथा शेष विश्व के साथ रिश्तों पर पड़ सकता है। बता रही हैं **अनीता इंदर सिंह**

भारत यदि सन 2020 में अपनी क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिति को मजबूत करना चाहता है तो उसे आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से अपने आपको बेहतर बनाना होगा। दो घरेलू घटनाओं, भारत के आर्थिक पराभव और नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) ने न केवल एशिया बल्कि विश्व भर में उसके कदम को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। इन घटनाओं ने अमेरिका, जापान, आसियान देशों, बांग्लादेश, ईरान और सऊदी अरब जैसे मित्र देशों तथा यूरोपीय संसद के साथ हमारे रिश्तों को सवालों के घेरों में ला दिया है।

भारत और अमेरिका के सामने चीन के रूप में एक साझा चुनौती है। इसके साथ ही साथ भारत को अपने नागरिकों की जीवन गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए प्रगति की बेहद आवश्यकता है। सीएए ने भारतीय नागरिकता के लिए धर्म को भी एक आवश्यक परीक्षा बना दिया है। ऐसा कानून तकनीकी रूप से उन्नत विश्व से मुकाबला करने में भारत की मदद नहीं करने वाला, भारत इससे सशक्त नहीं होगा। यह कानून केवल यही बात रेखांकित करता है कि किस तरह भारत 21वीं सदी में एक हिंदू बहुसंख्यकवादी राज्य बनाने की बनाने की दिशा में आगे बढ़ रह रहा है। हकीकत में यह यात्रा पीछे धकेलने वाली है। वर्ष 2004 के बाद कुछ वर्षों तक भारत दुनिया के तीन या चार सबसे तेज विकसित होते देशों में शामिल था। आज यह शीर्ष 40 में भी शामिल नहीं है। इतना ही नहीं भारत अपने सशस्त्र बलों का आधुनिकीकरण करने में भी नाकाम रहा और हिंद महासागर क्षेत्र में भी वह बिना अमेरिकी मदद के अपनी स्थिति बरकरार रखने में सक्षम नहीं है।

21वीं सदी में समुद्री शक्ति बड़ी ताकत बनने के लिए आवश्यक है। चीन की आर्थिक और सामरिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण पहल बेल्ट ऐंड रोड दिखाती है कि हिंद महासागर के अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में उसकी नौसैनिक पहुंच कितनी मजबूत हो चुकी है। उसे रूस और ईरान से समर्थन भी मिला है। ये वे मुल्क हैं जो भारत के मित्र हुआ करते हैं। परंतु भारत की तुलना में चीन के साथ उनके कारोबारी और निवेश संबंधी रिश्ते अधिक मजबूत हैं। किसी भी देश की विदेश नीति कई जटिल कारकों पर निर्भर करती है। चीन और रूस के बीच की सामरिक साझेदारी के पीछे अमेरिका के वैश्विक रसूख को चुनौती देने की समझ नजर आती है। यही कारण है कि वे हिंद महासागर में अपनी पहुंच बढ़ा रहे हैं। नवंबर 2019 में रूस ने चीन और दक्षिण अफ्रीका के साथ आशा अंतरीप में नौसैनिक अभ्यास किया। उसने 27 दिसंबर अपने यहां आए बांग्लादेशियों को दीमक कहकर पुकारा जिससे रिश्ते और खराब ही होने थे। पिछले दिनों बांग्लादेश के विदेश मंत्री और गृह मंत्री ने भारत की आधिकारिक यात्रा रद्द कर दी। विदेश मंत्री ए के अब्दुल मोमेन ने कहा कि सीएए भारत के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को कमजोर करता है और इससे उत्पन्न अस्थिरता पड़ोसी देशों को प्रभावित कर सकती है। अन्य मित्रवत रहे मुस्लिम बहुल देश भी भारत का समर्थन नहीं कर रहे। गत सितंबर में भारत ने सऊदी अरब को एक मूल्यवान मित्र बताया था क्योंकि वह देश के ऊर्जा क्षेत्र में 100 अरब डॉलर का निवेश करना चाहता था। लेकिन अब खबर है कि सऊदी विदेश मंत्री की पाकिस्तान के विदेश मंत्री के साथ टेलीफोन पर बातचीत में कश्मीर मसले का भी जिक्र हुआ।

अमेरिका भारत का सबसे बड़ा रणनीतिक साझेदार है। परंतु देश की अर्थव्यवस्था में आ रही गिरावट, भारत के सैन्य आधुनिकीकरण न कर पाने तथा उसके संरक्षणवादी रुख के कारण कारोबार में गिरावट के कारण यह रिश्ता भी प्रभावित हुआ है। एमेजॉन द्वारा भारत में निवेश की पेशकश पर भारत के आधिकारिक रुख से भी भारत की कारोबार के अनुकूल होने की प्रतिष्ठा बढ़ेगी नहीं। इसके अलावा कश्मीर और सीएए पर भारत के रुख ने भी अमेरिका और यूरोप के सांसदों के बीच आधुनिक लोकतांत्रिक देश होने की उसकी छवि को प्रभावित किया है।

अमेरिकी कांग्रेस में भारत के लोकतंत्र को लेकर जो सवाल उठे उन्हें आसानी से खारिज नहीं किया जा सकता। कांग्रेस के सदस्य चाहें तो भारत को हथियारों की बिक्री रुकवा सकते हैं या प्रतिबंध भी लागू कर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत एस-400 मिसाइल सिस्टम की रूस से खरीद करेगा। अंतरराष्ट्रीय इतिहास पर नजर डालें तो वह भी बताता है कि किसी देश की को चीन और ईरान के साथ होरमुज जलडमरूमध्य में अभ्यास किया। दुनिया के कुल तेल परिवहन का पांचवां हिस्सा यहां से गुजरता है। प्रतिबंधों से प्रभावित ईरान अब यह दावा कर सकता है कि हिंद महासागर में उसके पास दो ताकतवर मित्र हैं। रूस पश्चिम एशिया में अहम भूमिका निभा सकता है जबकि चीन अपनी नौसैनिक शक्ति प्रदर्शित कर रहा है। इस बीच भारत ने कई वर्ष की बातचीत के बाद अंतिम क्षणों में क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (आरसेप) से बाहर रहने का निर्णय लिया। यह दक्षिण पूर्व और पूर्वी एशिया में उसकी छवि के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। एशिया के बहुपक्षीय व्यापार समझौतों से बाहर रहकर भारत इस क्षेत्र के आर्थिक भविष्य में क्या योगदान दे पाएगा? देश की अर्थव्यवस्था डूब रही है। वह आसियान देशों, जापान और दक्षिण कोरिया से पीछे है, ऐसे में चीन का मुकाबला करने की बात मुश्किल ही है।

सीएए भी मित्र राष्ट्रों के साथ भारत के रिश्तों में मुश्किल की वजह बना है। सीएए पारित होने के बाद दिसंबर में पूर्वोत्तर भारत में हिंसा भड़कने के पश्चात भारत के मित्र माने जाने वाले जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपनी वार्षिक बैठक रद्द कर दी थी। पड़ोसी देश बांग्लादेश भी सीएए से आहत है। भारत ने आर्थिक कमजोरी और सामाजिक-राजनीतिक तनाव का लाभ विदेशी मुल्क उठाते हैं।

भारत के आर्थिक कद में आ रही कमजोरी और समाज में बढ़ता ध्रुवीकरण अमेरिका, जापान और आसियान देशों को यह मौका प्रदान कर रहे हैं कि वे उसकी बड़ी एशियाई शक्ति बनने की क्षमता पर सवाल उठा सकें। जबरदस्त राजनीतिक बहुमत वाली सरकार होने के बावजूद अर्थव्यवस्था में नई जान फूंकने और सामाजिक आर्थिक हालात को स्थिर करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा सीएए भी देश के लोकतांत्रिक मित्रों मसलन अमेरिका और जापान आदि को नाखुश कर रहा है। वहीं सऊदी अरब जैसे अधिनायकवादी देश भी इसका समर्थन नहीं कर रहे। आर्थिक क्षेत्र में ये सभी देश भारत के लिए महत्त्वपूर्ण हैं। अमेरिका का महत्त्व सबसे अधिक है। यूरोपीय संसद ने सीएए की आलोचना की है। यह बात यूरोपीय संघ और भारत की बैठक पर असर डालेगी। क्या देश की आर्थिक गिरावट और सामाजिक राजनीतिक स्थिति देश के मित्रों के साथ उसके रिश्ते जोखिम में डाल रहे हैं?

(लेखिका सेंटर फॉर पीस ऐंड कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्यूशन, नई दिल्ली की संस्थापक प्रोफेसर हैं)

पुराने मुद्दों से नहीं उबर पाए भारत और श्रीलंका के संबंध

सियासी हलचल

आदिति फडणीस

कुछ चीजें नहीं बदलती हैं। शायद वे बदली भी नहीं जा सकतीं। श्रीलंका के राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे भारत की यात्रा पर आए। उनकी पांच दिन की यात्रा मंगलवार को संपन्न हो गई। श्रीलंका के मीडिया, खासकर तमिल भाषा के समाचार माध्यमों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान को प्रमुखता दी गई, जिसमें उन्होंने कहा कि वह 'इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि श्रीलंका सरकार एकीकृत श्रीलंका में तमिल मूल के लोगों की समानता, न्याय एवं शांति की अपेक्षाओं को समझेगी।' हालांकि श्रीलंका के प्रधानमंत्री ने मीडिया के समक्ष दिए बयान में तमिल मुद्दे का बिल्कुल जिक्र नहीं किया। राजपक्षे ने इनसे इतर आर्थिक, शैक्षणिक एवं कौशल विकास, रक्षा और खुफिया जानकारियां साझा करने में द्विपक्षीय सहयोग पर अधिक जोर दिया।

राजपक्षे ने कहा, 'मैं प्रधानमंत्री मोदी से आग्रह करता हूं कि वह श्रीलंका के सभी हिस्सों में आवासीय परियोजना के विस्तार में और सहायता मुहैया कराएं। इससे देश के ग्रामीण हिस्सों में रहने वाले कई लोगों को लाभ मिलेगा।' जो तमिल मूल के लोगों के लिए विशेष घोषणाओं की उम्मीद कर रहे थे, उन्होंने पाया कि राजपक्षे के बयान में सभी के लिए आवास पर जोर दिया गया है, न कि जाफना में रहने वाले तमिल क्षेत्रों के संबंध में खास तौर पर यह बात कही गई है। जाफना में भारत ने हजारों विस्थापित तमिल लोगों के लिए आवास बनाए हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो श्रीलंका लगातार इस बात से इनकार करता रहा है कि उसे अल्पसंख्यक तमिलों को लेकर किसी तरह की समस्या पेश आ रही है। दूसरी तरफ, भारत लगातार श्रीलंका को तमिल लोगों से जुड़ी समस्या सुलझाने की सलाह देता रहा है।

यात्रा की पृष्ठभूमि

राजपक्षे की भारत यात्रा से ठीक पहले एक सोची-समझी रणनीति के तहत कुछ निर्णय लिए गए थे। पिछले सप्ताह श्रीलंका के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर तमिल भाषा में राष्ट्रीय गान गाने की अनुमति नहीं दी गई। ऐसा नहीं है कि यह पहली बार हुआ है, लेकिन इसमें श्रीलंका के उत्तर एवं पूर्व में रहने वाले तमिल मूल के लोगों और भारत सरकार के लिए स्पष्ट संदेश था कि नई सरकार समस्त श्रीलंका को ध्यान में रखकर आगे बढ़ रही है और वह इसी रणनीति के साथ आगे बढ़ेगी। भारत ने भी श्रीलंका सरकार के इस स्पष्ट संदेश को भांप लिया और राष्ट्रीय गान से जुड़े कदम पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। भारत ने इसे श्रीलंका का आंतरिक मामला मान कर इसमें हस्तक्षेप करने से स्वयं को अलग रखा।

पिछले महीने राजपक्षे ने चीन के सहयोग से बने 269 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली कोलंबो मेगा पोर्ट सिटी का उद्घाटन किया और इसे भविष्य का वित्तीय केंद्र घोषित कर दिया। उन्होंने इस बात को भी नकार दिया कि उनका देश चीन के कर्ज जाल में फंसता जा रहा है। भारत वास्तव में आर्थिक एवं तकनीकी सहयोग समझौते पर किसी तरह की पहल की उम्मीद नहीं कर रहा था। इस समझौते का मकसद एफटीए की त्रुटियां दूर करना और सेवाओं एवं तकनीक हस्तांतरण के कारोबार पर समझौता करना था। इससे आर्थिक एवं व्यापार संबंधों को एक नया आयाम मिलता। राजपक्षे की यात्रा में ऐसा कुछ नहीं हुआ। दूसरे शब्दों में कहें तो राजपक्षे ने यह लगभग स्पष्ट कर दिया कि श्रीलंका राजनीति एवं सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन चीन आर्थिक विकास में उनका पसंदीदा सहयोगी है।

राजपक्षे ने यह बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी कि उन्हें भारत से किस तरह की उम्मीदें हैं। उन्होंने कहा, 'मैं राष्ट्रपति गोटाभाया राजपक्षे की बात दोहराना चाहूंगा कि पिछले साल अप्रैल में देश में जिस तरह से घटनाक्रम हुए उसके बाद हमें अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा नीति पर दोबारा विचार करना पड़ा और इस दिशा में भारत का सहयोग सराहनीय होगा। ईस्टर के दिन हुए एक के बाद एक बम विस्फोट के बाद प्रधानमंत्री मोदी को श्रीलंका आने के लिए मैंने धन्यवाद दिया। उनके दौरे से हमें इस भीषण त्रासदी से जूझने की असीम शक्ति मिली। श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को सहायता देने के लिए 40 करोड़ डॉलर के ऋण की प्रधानमंत्री मोदी की पेशकश का भी हम स्वागत करते हैं। हमें आतंकवाद से लड़ने के लए भी भारत से 5 करोड़ डॉलर की सहायता मिली है। हमने सहयोग के उन प्रस्तावों पर भी चर्चा की, जो राष्ट्रपति गोटाभाया के नवंबर दौरे में रखी गई थीं।' राष्ट्रपति गोटाभाया राजपक्षे नवंबर में भारत दौरे पर आए थे।

आगे की राह

श्रीलंका में इस साल अगस्त में आम चुनाव होने वाले हैं, लेकिन वहां के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति मार्च में संसद भंग कर नए चुनाव करा सकता है। देश के राष्ट्रपति रह चुके महिंदा राजपक्षे इस समय अंतरिम प्रधानमंत्री एवं वित्त मंत्री हैं। उनकी लोकप्रियता श्रीलंका के सिंहली बहुल दक्षिण भाग में सर्वोच्च स्तर पर है। ऐसा माना जा रहा है कि इस लोकप्रियता के दम पर श्रीलंका पोडुजना पेरामुना (एसएलपीपी) 225 सदस्यीय संसद के चुनाव में धमाकेदार प्रदर्शन करेगी। इससे सरकार के लिए अल्पसंख्यकों के अधिकारों में कमी करने संबंधी कानून पारित कराना आसान हो जाएगा। मौजूदा मंत्रिमंडल में कोई भी तमिल या मुस्लिम प्रतिनिधि नहीं है। एक बात तो अब साफ दिख रही है। श्रीलंका का रवैया अब एक राष्ट्र के तौर पर नरम नहीं रहेगा और अल्पसंख्यकों को अधिक संदेह की दृष्टि से देखा जाएगा। दूसरी तरफ नई सरकार के लिए सिंहली बहुत बौद्ध धर्मावलंबियों की अपेक्षाओं पर खरा उतरना आसान नहीं होगा। क्या वहां की सरकार यह बात जेहन में रखेगी कि वह इसी समुदाय के समर्थन की बदौलत सत्ता में आई है? या क्या यह धीरे-धीरे लेकिन निश्चित तौर पर उस राजनीतिक विचार पर अंकुश लगाने का प्रयास करेगी, जो अधिक मुखर हो रहा है? श्रीलंका में राजनीति अब पहले के मुकाबले अधिक पेचीदा होने वाली है।

कानाफूसी

बदलेगा कलेक्टर पद का नाम

मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के बाद कमल नाथ ने एकदम शुरुआती दौर में कहा था कि वह कलेक्टर का पद नाम बदलना चाहते हैं क्योंकि यह उपनिवेशकालीन नाम है। उन्होंने कहा था कि ब्रिटिश राज में कलेक्टर राजस्व संग्रह का काम करते थे और इसीलिए उनको यह नाम दिया गया था। अब एक वर्ष से अधिक समय बीतने के बाद नाथ ने इसके लिए एक समिति का गठन किया है। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी आईसीपी केशरी की अध्यक्षता वाली यह समिति सरकार को कलेक्टर के कुछ वैकल्पिक नाम सुझाएगी। अतीत में सरकार के सामने जिला प्रशासक और जिलाधीश जैसे कुछ नाम आए लेकिन इन पर सहमति नहीं बन सकी। देश के अधिकांश राज्यों में अब कलेक्टर के स्थान पर जिला मजिस्ट्रेट पद नाम का प्रयोग किया जाता है।

मंदी से इनकार

भारतीय जनता पार्टी के एक और नेता ने मंदी को खारिज कर दिया है। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के सांसद वीरेंद्र सिंह ने देश और दुनिया की मंदी को खारिज करते हुए कहा कि दिल्ली में और दुनिया भर में मंदी की चर्चा चल रही है लेकिन अगर वास्तव में कोई मंदी होती तो हम कुर्ता और धोती पहनकर आए होते, न कि कोट और जैकेट। उन्होंने यह भी कहा कि अगर मंदी होती तो हम पैंट और पाजामा नहीं खरीद रहे होते। इससे पहले गत वर्ष नवंबर में केंद्रीय मंत्री सुरेश अंगड़ी ने अर्थव्यवस्था की स्थिति को लेकर विपक्ष की आलोचना को खारिज करते हुए कहा था कि हवाई अड्डे और ट्रेनें भरी हुई चल रही हैं और लोग शादियां कर रहे हैं और इससे यह साबित होता है कि देश की अर्थव्यवस्था अच्छी स्थिति में है।

आपका पक्ष

नवीकरणीय ऊर्जा से विकास संभव

ऊर्जा किसी भी देश के विकास के लिए जरूरी है। यह ऐसी ऊर्जा है जो प्राकृतिक स्रोतों पर निर्भर करती है। इसमें सौर ऊर्जा, भू-तापीय ऊर्जा, पवन, ज्वार, जल और बायोमास के विभिन्न प्रकारों को शामिल किया जाता है। तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या के भरण-पोषण और सुख-सुविधाओं के लिए संसाधनों की तेजी से खपत हो रही है। लेकिन इससे पर्यावरण प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन जैसी गंभीर समस्याएं जन्म ले रही हैं। जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते के अनुसार, भारत ने संकल्प लिया है कि वर्ष 2030 तक बिजली उत्पादन की 40 फीसदी स्थापित क्षमता ऊर्जा के स्वच्छ स्रोतों पर आधारित होगी। साथ ही यह भी निर्धारित किया गया है कि वर्ष 2022 तक 175 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित की जाएगी। इसमें सौर ऊर्जा से 100 गीगावॉट, पवन ऊर्जा से 60 गीगावॉट, बायो ऊर्जा से 10 गीगावॉट और छोटी पनबिजली परियोजनाओं से 5 गीगावॉट क्षमता शामिल है। भारत कुल स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता और सौर ऊर्जा के लिहाज से विश्व में पांचवें स्थान पर और पवन ऊर्जा के क्षेत्र में चौथे स्थान पर है। ऊर्जा भंडारण क्षेत्र में बेहतरी के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय ऊर्जा भंडारण मिशन तैयार किया गया है। इसे और अधिक प्रभावी तरीके से नवाचार एवं नीतिगत समर्थन पर केंद्रित करना होगा। हमें ऊर्जा क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास पर भी जोर देना होगा।

अनु मिश्रा, सीवान

भारत ने संकल्प लिया है कि वर्ष 2030 तक स्वच्छ ऊर्जा की क्षमता 40 फीसदी तक होगी

नए सिक्के लेने से न करें इनकार

आजकल कई जगहों पर लोग या दुकानदार सिक्के लेने से मना कर देते हैं। खासकर 10 रुपये के सिक्के लोग लेना नहीं चाहते हैं। इससे आम लोगों को सामाजिक व आर्थिक स्तर पर नुकसान झेलना पड़ रहा है। उत्तर भारत में यह समस्या ज्यादा विकट है। इससे आम लोगों में यह भाव उत्पन्न हो रहा है कि यह सिक्के अवैध तो नही हैं। कई मुख्य बैंक भी इन सिक्कों को लेने से इनकार कर देते हैं, जबकि रिजर्व बैंक भी समय-समय पर यह सूचना देता रहा है कि सभी सिक्के वैध हैं और अगर कोई इसे स्वीकार नहीं कर रहा तो इसे कानूनन अपराध माना जाएगा। इसलिए आम लोगों को इसके प्रति जागरूक करने की जरूरत है। इसमें शासन और प्रशासन के साथ-साथ जानकार लोगों को भी अपना योगदान देना चाहिए, ताकि देश और आम लोगों का नुकसान नहीं हो।

भूपेंद्र सिंह रंगा, पानीपत

स्वच्छता पर विशेष ध्यान जरूरी

कोरोनावायरस एक वायुजनित संक्रमण के कारण फैलने वाली बीमारी है। वायु जनित संक्रमणों की रोकथाम के लिए सामान्य स्वच्छता के उपाय बेहद जरूरी हैं। लोगों को व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखने पर जोर देना चाहिए। लोगों को हाथ कम से कम 20 सेकंड तक धोने और बीमार लोगों के संपर्क से बचना होगा। खांसने या छींकने के दौरान चेहरे को ढकने और यात्रा के दौरान या सार्वजनिक स्थानों पर काम करते समय मुंह पर मास्क लगाने चाहिए। कोरोनोवायरस की वजह से चीन में सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है। भारत में भी इसके मामले देखे जा रहे हैं। ऐसे में सरकार और लोगों को इसके प्रति जागरूक होना चाहिए।

कृपाशंकर दहेरिया, रायपुर

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

संक्षेप में

जनवरी में स्वर्ण ईटीएफ में 200 करोड़ का निवेश

स्वर्ण एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) में जनवरी में शुद्ध निवेश 200 करोड़ रुपये रहा है। यह सात साल का सबसे ऊंचा स्तर है। दुनिया के विभिन्न हिस्सों में उभरे भू-राजनीतिक तनाव और वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुस्ती को देखते हुए निवेशक सुरक्षित विकल्पों की ओर रुख कर रहे हैं। यह लगातार तीसरा महीना रहा जबकि स्वर्ण ईटीएफ में शुद्ध निवेश आया है। एसोसिएशन ऑफ म्युचुअल फंड्स इन इंडिया (एम्फी) के आंकड़ों के अनुसार जनवरी में स्वर्ण ईटीएफ में 202 करोड़ रुपये का शुद्ध निवेश हुआ। इससे पिछले महीने यह निवेश 27 करोड़ रुपये रहा था। नवंबर में इसमें 7.68 करोड़ रुपये का निवेश हुआ था। हालांकि, अक्टूबर में स्वर्ण ईटीएफ से 31.45 करोड़ रुपये की निकासी की गई थी। सितंबर में इन कोषों में 44 करोड़ रुपये और अगस्त में 145 करोड़ रुपये का निवेश हुआ था। स्वर्ण ईटीएफ में ताजा मासिक निवेश दिसंबर, 2012 के बाद का सबसे ऊंचा स्तर है। उस समय इसमें 474 करोड़ रुपये का निवेश हुआ था। *भाषा*

कोल इंडिया पिछले साल से अधिक उत्पादन करेगी

कोल इंडिया लिमिटेड इस साल पिछले वर्ष के उत्पादन आंकड़े को पार कर जाएगी। कोयला मंत्रालय के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि लंबी बारिश की वजह से दिपका खान में उत्पादन प्रभावित हुआ। इसके बावजूद कंपनी पिछले साल की तुलना में अधिक उत्पादन करने में सफल रहेगी। कोल इंडिया का 2018-19 में उत्पादन 60.68 करोड़ टन रहा था। उसकी बिक्री 60.81 करोड़ टन रही थी। कोयला मंत्रालय में सचिव अनिल कुमार जैन ने हैदराबाद में एनर्जीज 2020 सम्मेलन के मौके पर अलग से बातचीत में कहा, 'अक्टूबर तक कोल इंडिया का उत्पादन करीब आठ प्रतिशत कम रहा था। पिछले कुछ माह के दौरान उत्पादन सुधरा है। अब यह सिर्फ 3.5 प्रतिशत कम रह गया है।' सचिव ने कहा कि साल के अंत तक यह बढ़ जाएगा। पिछले साल की तुलना में उत्पादन वृद्धि प्रतिशत में काफी अच्छी रहेगी। घरेलू उत्पादन में कोल इंडिया की हिस्सेदारी 80 प्रतिशत से अधिक है। मॉनसून की वजह से अप्रैल-सितंबर के दौरान कंपनी का उत्पादन छह प्रतिशत घटकर 24.1 करोड़ टन रहा है। *भाषा*

पीटीए के दाम 10 फीसदी लुढ़के

सिंथेटिक धागा विनिर्माण का प्रमुख कच्चा माल होता है पीटीए

दिलीप कुमार झा
मुंबई, 11 फरवरी

सिंथेटिक धागा विनिर्माताओं को बड़ी राहत देते हुए इसका प्रमुख कच्चा माल प्यूरिफाइड टेरिफथैलिक एसिड (पीटीए) पिछले एक सप्ताह में 10 प्रतिशत तक सस्ता हो गया है। चीन में कोरोनोवायरस का प्रकोप फैलने के कारण वहां से आयात अस्थायी रूप से रोके जाने के बाद दामों में यह कमी आई है। सिंथेटिक धागे के इस कच्चे माल पर डंपिंगरोधी शुल्क वापस लिए जाने से भारत में यह सस्ता हो गया है। फिलहाल पीटीए का भाव लुढ़ककर 600 से 620 डॉलर प्रति टन के स्तर पर चल रहा है। करीब एक पखवाड़ा पहले पीटीए के दाम तकरीबन 660 से 700 डॉलर प्रति टन के स्तर पर थे। पीटीए के दाम कच्चे तेल के दामों के उतार-चढ़ाव से निर्धारित किए जाते हैं जो पिछले एक सप्ताह में 10 से 12 प्रतिशत तक गिर चुके हैं। कच्चे तेल के साथ जुड़े होने की वजह से घरेलू विनिर्माता भी पीटीए के दाम डॉलर रूप में बताते हैं।

सिंथेटिक धागा विनिर्माता पीटीए के दामों में इस गिरावट का श्रेय सरकार द्वारा 2.5 प्रतिशत का डंपिंगरोधी शुल्क समाप्त किए जाने को दे रहे हैं। 1 फरवरी को पेश किए गए आम बजट में इसका प्रस्ताव रखा गया था। इसके अलावा दुनिया के सबसे बड़े पीटीए निर्यातक चीन में घातक कोरोनोवायरस फैलने के कारण भी पीटीए के आयात में ठहराव आ गया है। भारतीय उत्पादकों के पास सिंथेटिक धागा विनिर्माताओं की आपूर्ति के लिए पर्याप्त स्टॉक है। इस कारण अस्थायी रूप से आयात रुकने के कारण पड़ने वाला असर निष्प्रभावी हो जाएगा।

करीब **50** लाख टन की स्थापित क्षमता के साथ बड़े कच्चे तेल रिफाइनर समेत भारतीय उत्पादक करीब **80** प्रतिशत पीटीए क्षमता का इस्तेमाल करते हैं

भारत में सस्ता

- पीटीए के दाम कच्चे तेल के दामों में उतार-चढ़ाव से किए जाते हैं निर्धारित
- कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आने से पीटीए में आई नरमी
- चीन में कोरोनोवायरस फैलने के कारण वहां से आयात अस्थायी रूप से हुआ बंद
- भारतीय उत्पादकों के पास सिंथेटिक धागा विनिर्माताओं के लिए है पर्याप्त स्टॉक
- इस कारण अस्थायी रूप से आयात रुकने का असर हो जाएगा निष्प्रभावी

फिलाटेक्स इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक मधुसूदन भगेरिया ने कहा कि चीन में कोरोनावायरस का प्रकोप फैलने के बाद से पीटीए की कीमतें लगभग 10 प्रतिशत तक गिर चुकी हैं। कच्चे तेल के दामों में गिरावट के अलावा डंपिंगरोधी शुल्क खत्म करने के भारत सरकार के कदम ने भी पीटीए की कीमतों में गिरावट में मदद की है। अन्य पॉलिमरों की कीमतों में भी गिरावट आई है। पीटीए पर डंपिंगरोधी शुल्क के रूप में उत्पादक हमसे प्रति टन करीब 30 से 40 डॉलर वसूल रहे थे जिसका लाभ अब उपभोक्ताओं को मिलेगा।

इस बीच विशेषज्ञों का मानना है कि पीटीए पर शुल्क समाप्त करने से सिंथेटिक धागा विनिर्माताओं के लाभ में इजाफा होगा। कच्चे माल की कम कीमत के कारण मांग बढ़ेगी और इसका लाभ उपभोक्ताओं को मिलेगा। सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद (टेक्सप्रोसिल) के चेयरमैन केवी श्रीनिवासन ने कहा कि पीटीए पर डंपिंगरोधी शुल्क खत्म करने से उद्योग को सस्ते दामों पर इसकी उपलब्धता में मदद मिलेगी और तैयार मूल्य संवर्धित उत्पादों में तेजी आएगी। इसके अलावा इस साल निर्यातित उत्पादों पर शुल्कों और करों में कटौती की योजना लाई जाएगी जिसमें बिजली शुल्कों और परिवहन के लिए इस्तेमाल ईंधन पर मूल्य संवर्धित कर (वैट) जैसे शुल्कों का रिफंड होगा। अब तक कपड़ा कंपनियों को ऐसे रिफंड नहीं मिलते थे। ऐसे लाभों से निश्चित रूप से निर्यात बाजार में कपड़ा उत्पादों की प्रतिस्पर्धी क्षमता में काफी इजाफा होगा।

जब दाम कम होते हैं, तो कुछ अतिरिक्त मांग पैदा होती है। इसलिए सिंथेटिक कपड़ा विनिर्माताओं को अतिरिक्त मांग का लाभ मिलेगा जो आने वाली तिमाहियों में उनका मुनाफा बढ़ाने में मदद करेगी। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री (सीआईटीआई) के चेयरमैन टी राजकुमार का मानना है कि अगर भारत के कपड़ा उद्योग को वर्ष 2025 तक 350 अरब डॉलर वाले बाजार का आकार हासिल करना है, तो अपना कच्चा माल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी दामों पर उपलब्ध कराए बिना ऐसा नहीं किया जा सकता है।

तकरीबन 50 लाख टन की स्थापित क्षमता के साथ बड़े कच्चे तेल रिफाइनर समेत भारतीय उत्पादक करीब 80 प्रतिशत पीटीए क्षमता का इस्तेमाल करते हैं। चीन की 4.5 करोड़ टन उत्पादन क्षमता है जिसमें से 3.5 करोड़ टन की खपत स्थानीय स्तर पर होती है। शेष एक करोड़ टन का उपयोग निर्यात के लिए किया जाता है।

भारत के चीनी उत्पादन में बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं

रॉयटर्स
दुबई, 11 फरवरी

वर्ष 2019-20 में भारत के चीनी उत्पादन अनुमान में कोई बड़ा बदलाव होने की उम्मीद नहीं है। आज भारतीय चीनी मिल संघ (इस्मा) ने आंकड़ों की समीक्षा करते हुए कहा कि चीनी उत्पादन का अनुमान 2.6 करोड़ टन है जिसमें कोई बड़ा फेरबदल नहीं होगा। इस्मा के अध्यक्ष विवेक पिट्टी ने दुबई में एक औद्योगिक सम्मेलन में कहा कि 25 फरवरी को बैठक होगी। उन्होंने कहा कि अगर आप मुझसे पूछें तो मुझे कोई बड़ा बदलाव होता नहीं दिख रहा है।

दुनिया के सबसे बड़े चीनी उत्पादक देश के तौर पर भारत का मुकाबला ब्राजील से होता है। वर्ष 2018 में सूखे के कारण भारत में किसान गन्ने की बुआई में कटौती करने को मजबूर हुए थे, जबकि वर्ष 2019 में गन्ने की खेती वाले प्रमुख क्षेत्रों में बाढ़ के कारण फसलों को नुकसान पहुंचा था। औद्योगिक संगठन ने कहा कि इसके नतीजतन वर्ष 2019-20 में देश का चीनी उत्पादन 21.6 फीसदी घटकर 2.6 करोड़ टन के साथ तीन साल के सबसे निचले स्तर पर आ गया।

अपने उत्पादन अनुमान के संबंध में इस्मा ने महाराष्ट्र के 62 लाख टन उत्पादन को भी ध्यान में रखा है। पिट्टी ने कहा कि यह मामूली रूप से बढ़कर 65 लाख टन तक जा सकता है। इस्मा ने यह भी अनुमान जताया है कि 2019-20 सत्र के दौरान आठ लाख टन से अधिक गन्ने का इस्तेमाल एथनॉल बनाने के लिए किया जा सकता है। यह पिछले सीजन के मुकाबले पांच लाख टन से अधिक है।

इस्मा के महानिदेशक अविनाश वर्मा ने कहा, 'भारत के पास काफी मात्रा में अतिरिक्त गन्ना और अतिरिक्त कच्चा माल है जिसका इस्तेमाल एथनॉल के लिए किया जा सकता है।' उन्होंने कहा कि यदि देश में पर्याप्त क्षमता में एथनॉल तैयार किया जाता है तो इसके लिए और अधिक मात्रा में गन्ना दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि देश में एथनॉल की मौजूदा क्षमता 3.5 अरब लीटर है जो जरूरी 5.11 अरब लीटर से बहुत कम है।

इस्मा ने कहा कि उसे देश की चीनी निर्यात नीति में कोई बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है। पिछले साल सरकार ने बड़ी मात्रा में उपलब्ध देश का चीनी भंडार निपटाने के लिए 2019-20 के लिए 10,448 रुपये प्रति टन चीनी निर्यात की सब्सिडी मंजूर की थी।

- महाराष्ट्र का उत्पादन **65** लाख टन तक जा सकता है
- निर्यात नीति में नहीं होगा बदलाव, डब्ल्यूटीओ कोई मुद्दा नहीं
- फरवरी में एशियाई देशों से निर्यात में आ सकती है तेजी

भारत सरकार के इस फैसले के विरोध में प्रतिस्पर्धी उत्पादक देश ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया ने विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) में शिकायत की थी। रविवार को दुबई की अल खलीज शुगर कंपनी ने कहा था कि भारत सरकार की ओर से दी गई सब्सिडी ने अनुचित बाजार तैयार किया है। यह कंपनी बंदरगाह स्थित दुनिया की सबसे बड़ी चीनी रिफाइनरी का परिचालन करती है। इस बीच चीन की जिंस कारोबारी कंपनी कोफको इंटरनैशनल के भारतीय उपमहाद्वीप के प्रमुख (चीनी) रवि कृष्णमूर्ति ने कहा कि इस एशियाई देश से चीनी निर्यात में फरवरी में तेजी आ सकती है।

वैश्विक चीनी खरीदार भारत से होने वाले बहुचर्चित चीनी निर्यात को अब तक अमलीजामा नहीं पहनाए जाने को लेकर हैरान हैं। चीनी की वैश्विक कीमत दो से ढाई वर्ष के शीर्ष स्तर पर होने के बावजूद भारत की कुछ मिलें चीनी बेचने की इच्छुक नहीं हैं। कृष्णमूर्ति ने कहा, 'अब तक की प्रगति को देखकर थोड़ा आश्चर्य हो सकता है क्योंकि निर्यात ठीक मात्रा में हो रहा है, चीनी की बिक्री की गई है और हम उम्मीद कर सकते हैं कि फरवरी में यह बढ़कर पांच लाख टन हो सकता है जो कि काफी अच्छी मात्रा होगी।'

अंतरराष्ट्रीय और घरेलू भाव

As on Feb 11	International Price	International %Chg#	Domestic Price	Domestic %Chg#
METALS ($/tonne)				
Aluminium	1,676.0	-7.1	1,977.8	3.2
Copper	5,659.5	-3.4	6,312.2	2.1
Nickel	12,880.0	-18.1	13,746.7	-18.8
Lead	1,810.0	-14.4	2,104.1	-1.7
Tin	16,350.0	-1.1	17,393.7	-0.5
Zinc	2,128.0	-16.2	2,412.7	-12.9
Gold ($/ounce)	1,569.6*	7.8	1,765.3	6.8
Silver ($/ounce)	17.7*	5.2	20.1	4.2
ENERGY				
Crude Oil ($/bbl)	53.9*	-13.6	54.3	-11.6
Natural Gas ($/mmBtu)	1.8*	-33.3	1.8	-32.9
AGRI COMMODITIES ($/tonne)				
Wheat	196.7	7.7	291.1	-1.7
Maize	182.3*	1.2	261.0	-5.3
Sugar	432.0*	29.8	490.4	0.7
Palm oil	712.5	11.8	1,138.2	13.0
Rubber	1,279.3*	-14.4	1,921.7	7.3
Coffee Robusta	1,263.0*	-5.6	1,809.5	-4.6
Cotton	1,510.2	6.5	1,575.2	0.4

* As on Feb 11, 20 1800 hrs IST, # Change Over 3 Months, Conversion rate 1 USD = 71.3& 1 Ounce = 31.1032316 grams.

Notes:
1) International metals, Indian basket crude, Malaysia Palm oil, Wheat LIFFE and Coffee Karnataka robusta pertains to previous days price. 2) International metal are LME Spot prices and domestic metal are Mumbai local spot prices except for Steel. 3) International Crude oil is Brent crude and Domestic Crude oil is Indian basket. 4) International Natural gas is Nymex near month future & domestic natural gas is MCX near month futures. 5) International Wheat, White sugar & Coffee Robusta are LIFFE future prices of near month contract. 6) International Maize is MATIF near month future, Rubber is Tokyo-TOCOM near month future and Palm oil is Malaysia FOB spot price. 7) Domestic Wheat & Maize are NCDEX future prices of near month contract, Palm oil & Rubber are NCDEX spot prices. 8) Domestic Coffee is Karnataka robusta and Sugar is M30 Mumbai local spot price. 9) International cotton is Cotton no.2-NYBOT near month future & domestic cotton is MCX Future prices near month tures.

Bloomberg chartMaker — Compiled by BS Research Bureau

एमसीएक्स

Name	Tovr (₹ Cr)	OI(000)
Agri commodity		
Cotton	20.6	38428
Oil and Oilseeds	337.5	77865
Spices	1.3	10
Metal(Feb 10)		
Metal- non ferrous	4940.5	47555
Metal- precious	7258.8	375
Oil and gas(Feb 10)		
Gas	2193.3	57891
Oil	15298.8	3544

एनसीडीईएक्स

Name	Tovr (₹ Cr)	OI(000)
Agri commodity		
Cotton	96.4	131413
Grains	129.8	92585
Oil and Oilseeds	572.1	433705
Others	122.8	62775
Pulses	117.8	45315
Spices	28.7	21647

एमसीएक्स बढ़ा/घटा

Name (Maturity)	Close	Day*
Gainers (* % Change)		
Kapas (Apr 30)	1056.5	0.5
Cotton (Feb 28)	19090.0	0.4
Silver Micro (Feb 28)	46255.0	0.3
Silver Mini (Feb 28)	46250.0	0.3
Silver (Mar 05)	46229.0	0.3
Nickel (Feb 28)	943.1	0.3
Losers (* % Change)		
Natural Gas (Feb 25)	126.5	-5.7
Cardamom (Feb 14)	3499.2	-2.5
Crude Oil (Feb 19)	3541.0	-2.1
Zinc (May 29)	170.6	-1.6
Crude Palm Oil (Feb 28)	730.1	-1.4
Lead Mini (Feb 28)	142.8	-1.3

एनसीडीईएक्स बढ़ा/घटा

Name (Maturity)	Close	Day*
Losers (* % Change)		
Jeera Unjha (Mar 20)	13645.0	1.0
CottonSeed Oil-Akola (Feb 20)	1771.0	1.0
Guar Seed 10 (Feb 20)	3840.0	0.6
Shankar Kapas-Rajkot (Apr 30)	1056.5	0.4
GuarGum 5T-Jodhpur (Feb 20)	6717.0	0.3
Losers (* % Change)		
Coriander-Kota (Apr 20)	6105.0	-1.0
Soyabean Indore (Feb 20)	3924.0	-0.5
Chana-Bikaner (Mar 20)	3924.0	-0.4
Barley Jaipur (Apr 20)	1690.0	-0.3
Ref Soy Oil-IDR-2016 (Feb 20)	843.2	-0.2
CastorSeed New-Disa (Feb 20)	3838.0	-0.2

एमसीएक्स बढ़त/छूट

Name (Maturity)	Futures	Prem/Dis
Premium over spot price (In %)		
Kapas Surendranagar (Apr 30)	1056.5	3.5
Cotton-Rajkot (Feb 28)	19090.0	1.1
Silver Micro-Ahemd (Feb 28)	46255.0	0.6
Silver Ahm (Mar 05)	46229.0	0.6
Gold Ahm (Apr 03)	40679.0	0.5
Aluminium Mum (May 29)	139.1	0.2
Discount over spot price (In %)		
Menthol Oil Chandaus (Feb 28)	1188.3	-10.0
Cardamom Vandanmedu (Feb 14)	3499.2	-8.3
Lead Min Mumbai (Feb 28)	142.8	-5.7
Nickel Mumbai (Feb 28)	943.1	-4.0
Lead Mum (May 29)	145.9	-3.6
Alumini-Mumbai (Feb 28)	136.4	-1.7

एनसीडीईएक्स बढ़त/छूट

Name (Maturity)	Futures	Prem/Dis
Premium over spot price (In %)		
Bajra-Jaipur (Feb 20)	1915.0	4.8
Bajra-Delhi (Feb 20)	1915.0	3.2
Maize-Sangli (Feb 20)	1861.0	2.1
Crude Palm Oil Kandl (Feb 28)	734.6	2.0
Paddy-Basmati-Karnal (Feb 20)	3130.0	1.0
Moong-Merta City (Feb 20)	7574.0	0.2
Discount over spot price (In %)		
Barley Jaipur (Apr 20)	1690.0	-20.9
Jeera Unjha (Mar 20)	13645.0	-4.7
Soy Bean Indore (Feb 20)	3924.0	-3.8
Coriander-Kota (Apr 20)	6105.0	-2.7
Guar Gum 5 MT-Jodhpu (Feb 20)	6717.0	-2.2

कल का हाजिर भाव

औद्योगिक

Metals	Mumbai
Aluminium utensil scrap /kg	105.....(105)
Aluminium ingots /kg	141.....(141)
Brass sheet cutting /kg	326.....(325)
Brass utensil scraps/kg	311.....(310)
Copper heavy scrap /kg	417.....(416)
Copper utensil scraps/kg	392.....(390)
Copper wire bar /kg	450.....(449)
Lead ingots /kg	150.....(150)
Nickel Cathodes /kg	980.....(970)
Tin slabs /kg	1240.....(1240)
Zinc slabs /kg	172.....(175)
Source:Bombay Metal Exchange	

Cotton	Mumbai
Bengal Deshi /Qtl	10151.....(10208)
DCH - 32 /Qtl	11332.....(11304)
Jaydhar /Qtl	9758.....(9758)
Shankar- 6 /Qtl	11079.....(11051)
Source:Cotton Association of India	

Oil	Mumbai
Castor FSG /10kg	831.....(831)
Castor Comm /10kg	821.....(821)
Ricebran oil/10kg	820.....(820)
Groundnut oil /10kg	1140.....(1140)
Linseed oil /10kg	900.....(900)
Karanji /10kg	800.....(800)
Palm oil /10kg	840.....(845)
Sunflower exp ref /10kg	880.....(885)
Sunflower oil exp /10kg	825.....(830)
Soyabean ref / 10kg	850.....(860)
Source:Bombay Commodity Exchange	

सॉफ्ट

Sugar	Mumbai
Mumbai M-30 /Qtl	3390-3602 .....(3382-3602)
Source:Bombay Sugar Merchants Association	

ऊर्जा

Crude Brent-$/Barrel	
NYSE Crude	50.24.....(49.57)
Brent Crude (UK)	53.66 .....(52.97)
Brent Crude (WTI)	49.57.....(49.57)
NYSE Natural Gas-$/Mmbtu	1.76.....(1.77)
Furnace/ 180 Cst $/bbl	286.4.....(282.16)
Naptha spot /Rs/MT	45170.....(45170)
LSHS spot/ M.T.	36150.....(36150)
Furnace Oil spot/ K.L.	33950.....(33950)
Source:Petroleum Bazaar.com	

सर्राफा

Gold	Mumbai
Standard (99.50 Purity) /10 gms	40461.....(40575)
Pure (99.90 Purity) /10 gms	40624.....(40738)
Silver.999/ kg	46025.....(46225)
Source:India Bullion & Jewellers Association	

@SPOT PRICE(MCX, NCDEX & ICEX)

Commodity	Unit	PClose	Price (₹.) Close
29 mm Cotton-Rajkot (N)	1 B	18784.80	18825.95
Alumini-Mumbai (M)	1 K	138.65	138.80
Bajra-Delhi (N)	1 Q	1880.00	1855.00
Bajra-Jaipur (N)	1 Q	1840.00	1827.10
Barley Jaipur (N)	1 Q	2138.45	2135.85
Cardamom-Vand. (I)	1 K	3758.00	3817.00
Castor Seed Disa (N)	1 Q	3980.80	3972.60
Castor Seed-Kadi (N)	X	3990.00	3967.50
Chana Bikaner (N)	1 Q	3949.15	3990.20
Chana Delhi (N)	1 Q	4150.00	4210.70
Chana-Akola (N)	X	3912.50	3925.00
Coriander-Gondal (N)	X	6125.00	6100.00
Coriander-Jaipur (N)	X	6190.00	6140.00
Coriander-Kota (N)	1 Q	6298.00	6274.75
Cotton Seed Oilck Ak (N)	1 Q	1831.20	1833.50
Cotton Seed Oilck Ka (N)	1 Q	1893.65	1888.90
Cotton-Kadi (N)	1 B	18907.50	18832.80
CPO-Kandla (M)	10 K	759.00	749.80
Crude Palm Oil Kandl (N)	10 K	732.60	720.40
Crude Palm Oil-KAKIN (N)	10 K	740.00	730.00
Diamond 0.3 - Surat (I)	1 CT	904.75	904.50
Diamond 0.5-Surat (I)	1 CT	1548.85	1547.45
Diamond 1-Surat (I)	1 CT	3450.45	3452.55
Gold Ahm (M)	10 G	40589.00	40468.00
Gold Guinea-Ahmedaba (M)	8 G	32602.00	32505.00
Gold Petal-Mumbai (M)	1 G	4074.00	4058.00
Guar Gum 5 MT-Jodhpu (N)	X	6876.80	6866.30
Guar Seed 10 MT-Jodh (N)	1 Q	3850.00	3867.85
Guarseed-Jodhpur (I)	1 Q	3892.00	3800.00
Gur Muzaffar Nagar (N)	40 K	1099.05	1100.50
Isabgulseed-Unjha (I)	1 K	103.40	103.80
Jeera Jodhpur-Jodhpu (N)	X	14900.00	14850.00
Jeera Unjha (N)	1 Q	14411.10	14325.00
Kachi Ghani Must Oil (N)	10 K	830.00	823.90
Kapas Kadi-Kadi (N)	X	1015.60	1011.00
Kapas-Rajkot (N)	X	1006.25	1008.65
Lead Mum (M)	1 K	152.40	151.40
Maize Kharif-Nizamab (N)	X	1820.00	1860.00
Maize Rabi-Gulabbagh (N)	1	2100.00	2041.50
Maize-Erode (N)	X	1805.00	1833.75
Maize-Feed/Ind- Gula (N)	1 Q	2100.00	2041.50
Maize-Feed/Ind-Delhi (N)	1 Q	2000.00	2010.00
Maize-Sangli (N)	X	1857.90	1823.35
Masoor Grain Bold In (N)	1 Q	4600.00	4650.00
Moong-Merta City (N)	1 Q	7562.50	7562.50
Mustardseed Alwar (N)	20 K	4231.00	4282.50
Nickel Mumbai (M)	1 K	970.70	982.10
Paddy-Basmati-Karnal (N)	X	3125.00	3100.00
Paddy-Basmati-Karnal (I)	1 Q	3160.00	3152.00
Pepper-Ernakulam (I)	1 K	328.20	331.65
Pepper-Kochi (N)	1 Q	33122.20	33250.00
R M Oil-Sriganganaga (N)	X	820.00	820.00
Rape mustards-Patan (I)	20 K	773.00	755.00
Rapeseed Must.Seed (N)	X	1880.00	1875.65
Raw Jute-Kolkatta (N)	X	5305.15	5366.65
RBD Palm Olein Kakin (N)	10 K	822.50	811.40
Ref Soya Oil Indore (N)	10 K	859.70	855.00
Ref Soya Oil Mum (N)	10 K	860.00	859.25
Ref Soya Oil Nagpur (N)	10 K	855.00	855.00
Rubber-Kochi (N)	1 Q	13575.00	13700.00
Rubber-Kochi/Ernak. (I)	1 Q	13375.00	13667.00
Silver M-Ahemdabad (M)	1 K	46205.00	45961.00
Soy Bean Indore (N)	1 Q	4089.00	4080.00
Soy Bean Kota (N)	1 Q	4020.00	3939.00
Soy Bean Nagpur (N)	1 Q	4191.50	4173.85
Soy Bean-Akola (N)	X	4100.00	4095.00
Soymeal Indore (N)	1 T	32500.00	32500.00
Soyoil-Indore (I)	10 K	870.00	855.00
Steel Long-Ghaziabad (I)	1 T	31470.00	31000.00
Steel Long-MGG (I)	1 T	31700.00	31020.00
Steel Long-Raipur (I)	1 T	29020.00	28530.00
Sugar M Delhi (N)	1 Q	3245.00	3235.00
Sugar M Grade-Kanpur (N)	1 Q	3380.95	3361.90
Sugar M Grade-Kolhap (N)	1 Q	3285.00	3293.65
Sugar M Kolkatta (N)	1 Q	3466.65	3466.65
Sugar M Muzaff (N)	1 Q	3275.25	3267.05
Sugar S-Kolhapur (N)	1 Q	3151.65	3151.65
Turmeric Nizamabad (N)	1 Q	5900.00	5878.15
Wheat Delhi (N)	1 Q	2202.50	2206.65
Wheat Kota (N)	1 Q	2177.80	2186.90
Wheat New Indore (N)	1 Q	2175.00	2187.50
Wheat New Kanpur (N)	1 Q	2090.00	2090.00
Wheat New-Rajkot (N)	1 Q	2190.00	2205.00
Yellow Peas Mum (N)	1 Q	5600.00	5500.00
Yellow Peas-Kanpur (N)	1 Q	5650.00	5800.00
Zinc Mumbai (M)	1 K	172.30	170.60

* as on Feb 10, 20

(M) MCX ,(N) NCDEX & (I) ICEX Spot prices

जिंस वायदा

DAY SESSION
दिवस सत्र (मंगलवार)

कृषि जिंस

Cotton

Name Exchange (Units) Maturity	Open, High Low Close	Qty	Trds	OI
Cotton MCX(1 B)				
Feb 28	19000, 19110, 19000, 19090	1186	188	27398
Mar 31	19290, 19370, 19290, 19340	421	73	8512
CottonSeed Oil-Akola NCDEX(1 Q)				
Feb 20	1757, 1782, 1747, 1771	7320	532	28140
Mar 20	1774, 1804, 1766, 1797	34190	2492	73560
Apr 20	1797, 1828, 1792, 1821	4070	356	19920
May 20	1823, 1850, 1816, 1845	840	78	5630
Jun 19	1886, 1886, 1873, 1881	540	51	600
Kapas MCX(20 K)				
Apr 30	1055, 1057, 1054, 1056.5	472	66	1060
Shankar Kapas-Rajkot NCDEX(20 Kg)				
Apr 30	1055, 1058, 1052.5, 1056.5	590	338	3563

Grains

Name Exchange (Units) Maturity	Open, High Low Close	Qty	Trds	OI
Barley Jaipur NCDEX(1 Q)				
Apr 20	1690, 1690, 1690, 1690	100	7	2480
May 20	1690, 1690, 1690, 1690	100	2	2230
Guar Seed 10 NCDEX(1 Qtl)				
Feb 20	3826, 3868, 3816, 3840	8295	709	14700
Mar 20	3866, 3910, 3854, 3884	23890	2664	68995
Apr 20	3900, 3944, 3900, 3918	1215	126	4060

Oil and Oilseeds

Name Exchange (Units) Maturity	Open, High Low Close	Qty	Trds	OI
CastorSeed New-Disa NCDEX(1 Qtl)				
Feb 20	3812, 3850, 3802, 3838	1420	185	6155
Mar 20	3850, 3888, 3830, 3878	3100	400	22185
Apr 20	3862, 3906, 3862, 3896	340	55	5645
Crude Palm Oil MCX(10 K)				
Feb 28	740.5, 743, 723.5, 730.1	25210	1661	45560
Mar 31	737, 739.9, 718.5, 723.5	15990	1063	24100
Apr 30	736.2, 739.3, 714, 719.2	3570	280	7960
Mentha Oil MCX(1 K)				
Feb 28	1194.4, 1194.5, 1185.5, 1188.3	75.6	174	168.84
Mar 31	1184, 1184, 1179, 1180.2	17.28	25	73.08
Mustard Seed Rape Oil NCDEX(1 Q)				
Feb 20	3975, 4003, 3963, 3974	1310	101	6030
Apr 20	4026, 4047, 3992, 4007	14450	1238	16840
May 20	4053, 4070, 4028, 4040	1480	120	3890
Ref Soy Oil-IDR-2016 NCDEX(10 Kg)				
Feb 20	846.6, 848, 837, 843.2	6835	677	21195
Mar 20	832.8, 833.8, 823, 826.8	11190	1432	54485
Apr 20	825.8, 826.6, 814.6, 819.2	2230	310	6990
May 20	815, 817, 815, 817	10	2	115

Name Exchange (Units) Maturity	Open, High Low Close	Qty	Trds	OI
Soyabean Indore NCDEX(1 Q)				
Feb 20	3954, 3978, 3884, 3924	13765	1333	30080
Mar 20	3930, 3958, 3856, 3910	47620	5777	146935
Apr 20	3936, 3960, 3852, 3908	16215	2172	94685
May 20	3958, 3970, 3874, 3930	2800	449	18100
Jun 19	3942, 3966, 3928, 3940	180	30	370

Others

| Name Exch

विपक्ष के लिए नया मॉडल

आदिति फडणीस

फोटोः दलीप कुमार

जीत के बाद लोगों को संबोधित करते अरविंद केजरीवाल

दिल्ली विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी (आप) की शानदार जीत के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता शरद पवार ने कहा कि दिल्ली चुनाव के नतीजे देश में बदलाव की बयार का संकेत दे रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र में उनकी पार्टी के साथ गठजोड़ कर सरकार बनाने वाले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने तो बड़ी साफगोई से कह दिया कि दिल्ली के लोगों ने 'मन की बात' के बजाय 'जन की बात' को चुन लिया। उन्होंने कहा, 'दिल्ली में ही राष्ट्रवादी विचारधारा वाली भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार है जिसने दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी लेकिन झाड़ू के सामने नाकाम साबित हुई।'

आम आदमी पार्टी ने दो सबसे अहम मुद्दे पर काम करते हुए ऐसी रणनीति बनाई जिसकी बदौलत उसे शानदार चुनावी जीत हासिल की। विपक्ष के लिए यह एक नया फॉर्मूला हो सकता है। चुनावी राजनीति में लोगों का मत जीतने का एक तरीका मुफ्त चीजें और सेवाएं देना है। आप की तरह ही तेलंगाना में भी तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) अपेक्षाकृत नई पार्टी है जो दिसंबर 2018 में लगातार दूसरी बार 25 सीटों और वोट हिस्सेदारी में 12 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ सत्ता में आई है। 2014 में टीआरएस को 119 सीटों वाले विधानसभा में 63 सीटें मिली थीं। टीआरएस ने भी गरीब परिवारों की लड़कियों की शादी (कल्याण लक्ष्मी/शादी मुबारक), नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य के लिए केसीआर किट्स (अम्मावोदी) और किसानों की मदद के लिए रैयत बंधु जैसी योजनाओं के दम पर सत्ता में दोबारा वापसी की।

केजरीवाल शाहीन बाग जैसे मुद्दों से दूर रहे लेकिन अल्पसंख्यक उनके साथ दिखे

शोध संस्था लोकनीति सीएसडीएस के चुनाव पूर्व आंकड़ों के मुताबिक टीआरएस सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को लेकर मतदाताओं के बीच काफी जागरूकता थी। इसकी वजह यह है कि इन योजनाओं को लागू करने के साथ-साथ घर-घर जाकर जनता को इनके बारे में बताया गया था।

टीआरएस ने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन (एआईएमआईएम) के साथ ही दोस्ताना ताल्लुकात बनाए रखा और मुसलमानों को शिक्षा और रोजगार में 12 फीसदी का आरक्षण देने का वादा करने के साथ ही मुस्लिम बच्चों के लिए आवासीय स्कूल भी खोले। इस तर्ज पर उत्तर प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी चुनावी सफलता पाई थी। उन्होंने बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर देने के साथ ही छात्रों को लैपटॉप भी दिया।

बिहार में भी नीतीश कुमार ने दूसरी बार सत्ता में इस वजह से वापसी की क्योंकि उन्होंने 2006 में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में विकास के काम किए। लड़कियों को साइकिल और पोशाक देने की वजह से स्कूली छात्रों की नामांकन तादाद पहले साल में ही 30 फीसदी से अधिक तक बढ़ गई। अध्ययन के मुताबिक इस योजना में भ्रष्टाचार 5 फीसदी से भी कम रहा। इसके अलावा पैथोलॉजी सेवाओं के लिए सब्सिडी देने, राज्य सरकार के अस्पतालों में सुधार करने के साथ ही डिजिटलीकरण के जरिये निगरानी की व्यवस्था की गई।

ऐसे में कल्याणकारी योजनाएं सरकारों के दोबारा निर्वाचन में अहम भूमिका निभाती हैं। ऐसा नहीं है कि सभी योजनाएं मुफ्त हों लेकिन कुछ योजनाएं महज नीतिगत फेरबदल से ही प्रभावी और सक्षम साबित हो जाती हैं। आप ने शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में इन प्रयोगों के जरिये महारत हासिल की। दिलचस्प बात यह है कि आप ने राष्ट्रवाद और धार्मिकता का भी एक वैकल्पिक रास्ता दिया।

मध्यप्रदेश और दूसरी जगहों पर कांग्रेस ने जहां सॉफ्ट हिंदुत्व की पर जोर दिया, वहीं अरविंद केजरीवाल ने हनुमान और गणेश को अपनाया। वह शाहीन बाग जैसे मुद्दों से दूर रहे लेकिन अल्पसंख्यकों ने उन्हें माफ कर दिया। ओखला से आप के उम्मीदवार अमानुतुल्ला खान ने विधानसभा चुनाव के सभी विजेताओं के मुकाबले भारी बहुमत से जीत हासिल की। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने कांग्रेस की हार पर कोई टिप्पणी किए बगैर ही दिल्ली की जनता को भाजपा के ध्रुवीकरण के एजेंडे को हराने के लिए सलाम किया।

आप के लिए चुनौतियों भरी होगी आगे की राह!

रुचिका चित्रवंशी

दिल्ली में जीत का जश्न मनाते आप समर्थक

दिल्ली चुनाव में तीसरी बार जीत दर्ज कराने के बाद आम आदमी पार्टी (आप) को अगले पांच वर्षों के लिए चौबीस घंटे पीने के पानी की उपलब्धता, निर्बाध बिजली आपूर्ति, यमुना की सफाई और महिलाओं की सुरक्षा के वास्ते 'मोहल्ला' मार्शल की नियुक्ति तथा सीसीटीवी कैमरे लगाने जैसी अहम घोषणाओं को पूरा करना काफी चुनौतीपूर्ण होगा। आप पार्टी ने 2020 के अपने चुनावी घोषणापत्र में जीतने पर दिल्लीवासियों को 10 'गारंटी' देने का वादा किया है। इनमें से कुछ योजनाओं को पिछले पांच वर्षों में किए गए कार्यों को आगे बढ़ाकर पूरा किया जा सकता है। जैसे प्रत्येक घर तक बिजली पहुंचाने के लिए भूमिगत केबल, प्रत्येक बच्चे के लिए विश्व स्तरीय शिक्षा सुविधाएं, सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं और प्रदूषण में वर्तमान स्तर से एक तिहाई कम पर लाना शामिल है।

पार्टी ने दिल्ली के कारोबारी समुदाय की मदद करने के लिए कई पहल शुरू की हैं। पार्टी फेरीवालों तथा सड़क पर सामान बेचने वालों के लिए कानूनी सुरक्षा प्रदान करने जैसे लुभावने वादे को पूरा करने का प्रयास करेगी। आप पार्टी के चुनावी घोषणापत्र में कहा गया, 'हम छह महीनों के भीतर वेंडिंग संबधी प्रमाणपत्र जारी करेंगे और सड़क पर सामान बेचने वालों को एमसीडी तथा दिल्ली पुलिस से बचाने के लिए अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता वाले कियोस्क लगाएंगे।'

हालांकि शहर में बाहर से आने वाले लोगों के साथ ही बढ़ती आबादी के चलते राज्य के बुनियादी ढांचे की क्षमता अपनी अधिकतम सीमा तक पहुंच गई है और यह केजरीवाल के लिए बड़ी चुनौती होगी। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा, 'कुछ अच्छा करने के उत्साह के बीच पार्टी द्वारा कुछ अनदेखे मुद्दों का समाधान नहीं किया गया। जैसे अनधिकृत क्षेत्रों में जल निकासी तथा सीवेज सुविधाओं का अभाव।'

आप ने अगले पांच सालों में अनधिकृत कॉलोनियों में नाली की दुरुस्त व्यवस्था करने जैसे बुनियादी बातों पर जोर देने के साथ ही झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वालों को पक्का मकान देने का वाद किया है। एक सरकारी अधिकारी ने बताया, 'यह सब आसान नहीं होगा। इन क्षेत्रों में कचरापेटी तक रखने की जगह नहीं है। सरकार के पास ऐसा करने के लिए पैसा है लेकिन इस पर अमल करना और नगर निगम तथा जल बोर्ड से समर्थन मिलना भी अहम होगा।'

केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली के लिए भाजपा का सबसे बड़ा तोहफा गाजीपुर का कूड़ा पहाड़ है जो ताजमहल की ऊंचाई को छू सकता है लेकिन आप की सरकार दिल्ली को कचरामुक्त करने का वादा करती है।

दिल्ली के सरकारी स्कूलों में प्रसन्नता और उद्यमशीलता पाठ्यक्रम शुरू करने के बाद ही अब देशभक्ति पाठ्यक्रम भी शुरू होगा। जहां तक बुनियादी ढांचे का सवाल है आप ने दिल्ली मेट्रो नेटवर्क के दायरे को 500 किलोमीटर तक बढ़ाने की योजना बनाई है और एक साल के भीतर ही 40 किलोमीटर की सड़क को दोबारा डिजाइन करने की परीक्षण योजना शुरू होगी। पार्टी का कहना है, 'हम बुनियादी ढांचे के विकास के लिए फंड का पर्याप्त आवंटन करेंगे और बाजार तथा औद्योगिक क्षेत्रों का उन्नयन करेंगे।' दिल्ली सरकार दिल्ली में संपत्ति मालिकों के हितों का ख्याल रखते हुए सर्किल दरों को वास्तविक बाजार कीमतों के अनुरूप ही तार्किक बनाने के लिए वृहद समीक्षा करेगी।